४५८०५०-०१०५४

(2)
3197
28/3/2012

सत्यमेव जयते

असंशोधित

12 MAR 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा

गै०स०प्रे०सं०...456...तिथि 28-3-12

टर्न-१४/अंजनी-दि० १२.०३.१२

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय-कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय-कार्य

ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों के उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्नप्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा ।

जनता दल, यूनाईटेड	- ८७ मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- ६७ मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	- १६ मिनट
कांग्रेस पार्टी	- ३ मिनट
लोक जन शक्ति पार्टी	- १ मिनट
सी०पी०आई०	- १ मिनट
निर्दलीय	- ५ मिनट
	कुल-१८० मिनट

माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

डॉ० भीम सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में ३१ मार्च, २०१३ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए २०,९५,९७,२१,०००/-(बीस अरब पनचानवे करोड़ सनतानवे लाख एक्कीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर क्रमांक-३४,३५ तक क्रमशः माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि एवं श्री अवधेश कुमार राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं, जिसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार राय, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अवधेश कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-'

"इस शीर्षक की मांग १०/- रूपये से घटाई जाय ।"

महोदय, इसलिए हम मांग करते हैं कि माननीय मंत्री और यह विभाग राशि तो काफी खर्च करने का काम कर रही है, खर्च के लिए राशि दे रही है लेकिन उस खर्चे का दुरूपयोग जिस रूप में हो रहा है, उसका जो लूट हुआ है, उसका हम दो-चार उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ । महोदय, भगवानपुर प्रखंड में हमारे यहां एक भगवानपुर-संजात पथ है, ६ साल पहले इस पथ की स्वीकृति हुई और वह ६ साल तक बना नहीं । २०१० में फिर से नया प्राक्कलन बनाकर

उस पथ को भेजा गया और वह स्वीकृत होकर आ गया । लेकिन महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विभाग के अन्दर कितनी लूट है ठेकेदारी का कि ठीकेदारों ने मैनेज किया और वीरपुर के साथ जो आया था वीरपुर का सड़क हो गया मैनेज, लेकिन भगवानपुर-संजात पथ की फाईल नहीं जा सकी, उसकी फाईल यही रह गयी और अभीतक उस पथ को ६ साल में नहीं बनाया गया । बड़ा-बड़ा गढ़ा हो गया है, जिसके कारण उस पथ पर चलना मुश्किल हो गया है । महोदय, एक हमारे क्षेत्र में पड़ता है बछवाड़ा-समसा पथ, उस पथ को बनाने में सरकार ने २४ करोड़ रूपया खर्च किया, गत साल यह सड़क बना और इस साल, जाकर के माननीय मंत्री जी या सरकार के कोई देख आवें, बड़ा-बड़ा गढ़ा बन गया है । कितनी लूट हो रही है, यह आप अन्दाजा कर लीजिए विक्रम भाई तो इस रूप में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है । महोदय, मैं आपको बताउं कि इस विभाग ने जो कुछ टेंडर का नियम बनाया, बड़े-बड़े ठीकेदार १००-१०० किलोमीटर रोड का टेंडर ले लिया और चार वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष पहले विभाग से इनको मोटी राशि मिल गयी और वह लेकर के सारे पथ का जो हालत बनना चाहिए था, उसका हालत बिगाड़ दिया । एक है नोयडा की कम्पनी बी०एन०ए० इनफ्रास्ट्रक्चर, २०११ के जून तक इस पथ को पूरा करना था, १००किलोमीटर पथ था । मेरे यहां १४ पथें हैं - ईशापुर से समस्तीपुर, आलमचक रोड से राजापुर राधो, गणपतैल से गेसपुर सोहिलवारा, जगदीशपुर से बुचौली, पी०डब्लू०डी० रोड मुशहरी, टी० ०४ से चमथा कुर्मी टोल, चमथा बड़खुट चमथा घाट, झमटिया घाट से चमथा गोपालपुर, आर०ई०ओ० से आजादनगर, एन०एच० २८ रचियाही, एन०एच० २८ से रसिदपुर, टी० ०२ से झमटिया, एन०एच० २८ से शिबुटोल पुराना, एच०एच०२८ से शिबुटोल, कुल १४ पथ हैं, सारे पथ में मिट्टी डाल दिया गया और पथ का जो शक्ल था, उसको बिगाड़ दिया, अब उसमें चलना मुश्किल हे । १०० किलोमीटर पथ एक जिला में इस तरह से एक ठीकेदार ने इस तरह का कार्य किया और इसपर कोई अंकुश नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़ नहीं ? सरकार रोज कहती है कि हम केस करेंगे, फिर ये केस करेंगे, फिर ये रि-टेंडर करेंगे, फिर वही ठीकेदार का कोई दूसरा चला आयेगा और लूट करके चला जायेगा । महोदय, इसका टेंडर २००९ में हुआ, इसको पूरा करना था जून २०११ में, कम्पलीट करके देना था, हेंडओवर करना था लेकिन अभीतक नहीं हुआ । महोदय, मैं आपको बताउं कि इसी तरह से दूसरा जो बाहर का नहीं है, यहीं की कम्पनी है, उसमें कई ऐसे पथ हैं, १०० किलोमीटर के ज्यादे का पथ, जिस पथ का पैसा लेकर वही हालत किये हुए हैं, जो नोयडा की कम्पनी किये हुए है । एक चौधरी कनस्ट्रक्सन है जो एन०एच-२८ से सूरो, एन०एच०-२८ से चिड़ंजीपुर, एन०एच०-२८ से तेमुहाँ, पी०डब्लू०डी० से काजी रसलपुर । एक हैं एस०एम०टी०प्राईवेट लिमिटेड हैं, उसमें एन०एच० २८ से बछवाड़ा, पी०डब्लू०डी० से दशरथपुर, भवानपुर धकजरी तकिया, जगदीशपुर बनवारीपूर, रानी पश्चिम, फतेहा, रूदौली जहानपूर भरौल, यह चारों पथ लगभग

१०० किलोमीटर पथ है, इन सारे पथों की भी यही स्थिति है । महोदय, इसके अलावे नयी बात को छोड़ दीजिए, पिछला एक साल बीत गया, एक भी पथ नया इस विभाग के द्वारा नहीं लिया गया । लगभग १०० से १५० किलोमीटर पथ, ऐसा जर्जर हालत में है, उसमें चलना मुश्किल है । इसलिए महोदय, इस विभाग के अन्दर ठीकेदारी लूट, ठेकेदारों पर कोई नियंत्रण नहीं, विभागीय पदाधिकारियों की कोई चिंता नहीं, विभागीय पदाधिकारियों को परसेंटेज मिले, बात चल जाता है और इन सब चीजों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमने विभाग की मांग को कटौती के रूप में पेश किया है । हम आशा करेंगे कि सरकार अगर चाहती है कि पैसे का सदुपयोग करे, ठीकेदारी लूट से बचाये, अफसर की मनमौजी को रोके, तभी विकास के काम हो सकते हैं । आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । ग्रामीण कार्य विभाग, ८९ परसेंट आबादी जो गांव में रहती है, उसके लिए लाईफ लाईन का काम करती है । ग्रामीण कार्य के बगैर गांव के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है । हरेक चीज ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ी हुई है ।

(क्रमशः)

टर्न-15/12.3.12/

श्रीरमण/

(5)

श्री अशोक कुमार सिंह : ... क्रमशः ...

पिछले छः साल में जो स्थिति थी ग्रामीण सड़कों की पुल पुलिया की, लोग गांव से पलायन करके शहर की ओर भाग रहे थे और जब शहर में आते थे तो यहां इनके बड़े बड़े गुंडे रहते थे, किडनैपर रहते थे, वो राज्य छोड़कर चले जाते थे तो गांव से शहर और शहर से भी बाहर, स्टेट से भी बाहर चले जाते थे, आज वह समय बदल गया, माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमारजी के नेतृत्व में सरकार बनी और ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण पुल पुलिया तेजी से बनना शुरू हुआ इनके समय में अलकतरा घोटाला होता था,इनके मिनिस्टर अलकतरा पीते थे रोड पर नहीं लगाया जाता था, तो वह आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और आज स्थिति ये है महोदय, हमलोग भी गांव में पले बढ़े हैं वहीं से पढ़े लिखे हैं, हमने देखा है, महसूस किया है कि अगर कोई एक व्यक्ति गांव में अगर बीमार पड़ जाय तो उसको खाट पर ले जाना पड़ता था ये हालत थी तो आज वह स्थिति बदल गयी है, एन0डी0ए0 की सरकार माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और हमें याद है तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी जब बिहार आये थे तो उन्होंने बिहार की सड़कों पर एक कमेंट किया था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता है तो इनके सुप्रीमो ने एक मजाक के लहजे में पूरे देश की महिलाओं का मजाक उड़ाया था एक ऐक्ट्रेस का नाम लेकरके कि हम फलां ऐक्ट्रेस के गाल जैसी सड़कें बना देंगे तो वो तो उन्होंने नहीं किया, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्रीजी, नीतीश कुमारजी माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदीजी की सरकार ने महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण देकर सम्मान देने का काम किया और पूरे बिहार की ग्रामीण सड़कें और शहर की सड़कें बनाने का भी काम किया है । तो इनके समय में हरेक चीज चाहे बिहार की सड़कें हों, महिलाएं हों मजाक उड़ाया जाता था और आज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यक्रम चल रहा है, उससे जो सड़कें बचेंगी उसमें माननीय मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री अवशेष ग्राम सड़क योजना के नाम से एक योजना बनायी है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो सड़कें बचेंगी और 250 बसावट वाले गांव भी मुख्य सड़क से जोड़े जायेंगे, ये हमारी सरकार ने, माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा किया है । आज महादलित टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है ये बहुत सारी जगहों पर जोड़ा जा चुका है और काम चल रहा है । आज हमारे मुख्यमंत्रीजी ने एक सपना देखा था कि बिहार के किसी भी कोने से छः घंटे में पटना पहुंचने का वो आज ग्रामीण कार्य विभाग उस सपना को साकार कर रही है । आज हमलोग किसी भी कोने से किसी गांव देहात से भी छः घंटे के अंदर पटना पहुंच रहे हैं ये हमारे विपक्ष के सदस्य भी महसूस करते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

अबतक हमारी सरकार करीब 24219 किलोमीटर लगभग ग्रामीण सड़कें बना चुकी हैं, 27500 किलोमीटर पर काम चल रहा है और करीब अभी 22000 किलोमीटर अतिरिक्त ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने की और जरूरत है जिसमें पी0एम0जी0एस0वाई0 से कोशिश की जा रही है, उसको कोर नेटवर्किंग से जोड़ा जा रहा है । तो और वो 22000 किलोमीटर जब सड़कें बन जायेंगी तो प्रदेश के सभी पंचायत पी0एम0जी0एस0वाई0 से जुड़ जायेंगे इससे हमारे राज्य का विकास बहुत तेजी से हो सकेगा । हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 13500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है जिसपर 5000 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है, जो तेजी से इस वित्तीय वर्ष में किया जायेगा और ग्रामीण सड़कें, हमने एक बात कही कि लाईफ लाईन, ग्रामीण कार्य विभाग लाईफ लाईन बहुत मायने में है, आज हमारी सरकार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है जिसमें ग्रामीण सड़कें, पंचायत भवन और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क बनने से आज गांव में लोग रहने लगे हैं, गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे पनपने लगे हुैं और हमलोग आसानी से जो पहले लोग गांव से भागते थे आज गांव में जाकर बसने लगे हैं तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव की ओर हम जा रहे हैं । शहर की ओर जा रहे थे अब हमलोग गांव की ओर चल रहे हैं और उसमें हमलोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योग धंधे, रोजगार के अवसर नौजवानों को वहां मिल रहा है, किसी भी चीज के लिये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, गांव में अगर हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, डेयरी का धंधा करते हैं तो उसको शहर पहुंचाने के लिये रोड, पुल पुलिया बहुत जरूरी है । वह ग्रामीण कार्य विभाग माननीय मंत्रीजी के नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में सकुशल ढंग से काम कर रही है ।

मैं एक अपने क्षेत्र की बात माननीय मंत्रीजी को घ्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि रफीगंज विधान सभा में मदनपुर प्रखंड में हिरियामा मोड़ से चितरसारी मोड़ तक 13 किलोमीटर लगभग इरकॉन द्वारा काम कराया जा रहा है जिसमें पांच किलोमीटर ही काम हुआ और काम बंद है तो हम आग्रह करेंगे कि उसका काम पूरा करवाया जाय और हमारे ही क्षेत्र का 4515 नाबार्ड से एन0एच02 से दधपुर मोड़ से देउजरा तक अधूरा काम है, उसको भी पूरा कराने का आग्रह करेंगे और एक आग्रह करेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क है रफीगंज प्रखंड में कासमा से नारायज भिखनपुरा पांती प्राणपुर होते सिरूआ तक पथ लगभग सात किलोमीटर ये महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कें हैं इनको भी माननीय मंत्री से हम आग्रह करेंगे कि प्राथमिकता में रख करके इसको बनवाया जाय । हमारे घर के बगल में, हमारे पंचायत के बगल में एक बलिगांव में केसर

नदी है उसपर पहले भी हमने आग्रह किया है, फिर मैं आज इस माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वो पुल का भी निर्माण कराया जाय । एक और रफीगंज गोह पथ में एक गड़बड़ी है 2005-06 में उसका टेंडर हुआ था, रफीगंज गोह पथ में उसमें सिहुली मोड़ से लट्टा तक 8 किलोमीटर का है जिसमें काम अधूरा है और 55 लाख रूपया का काम हुआ है और 58 लाख रूपया निकाल लिया गया है, उसकी भी जांच कराने की मांग करते हैं । तो इस तरह की कुछ हैं और हमारे बगल के शेरघाटी विधान सभा के एक दो और है, वह भी नक्सल प्रभावित है और बिहार झारखंड से जोड़ता है ये पुल बनाने की भी मांग करते हैं, अमारूत एवं महकमपुर के पास नीलांजन नदी पर बड़ा पुल का निर्माण, पोठवारा एवं बरिया के सामने नदी में बड़ा पुल का निर्माण और पीड़ासीन के पास फल्गु नदी पर पुल का निर्माण ये हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से और मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य,श्री मोतीलालजी ।

श्री मोतीलाल प्रसाद : सभापति महोदय,मैं वित्तीय वर्ष 2012-13 जिसका समापन 31 मार्च,2013 तक होना है ग्रामीण कार्य मंत्री द्वारा लाये गये मांग प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूं । विपक्ष के विधायक माननीय अवधेश कुमार राय और ज्योति रश्मि द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के मैं विरोध में खड़ा हूं । सभापतिजी, कटौती प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य हमें दिखायी नहीं पड़ता। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है । गांव में रहनेवाला एक सामान्य व्यक्ति भी यह सहज रूप में स्वीकार कर रहा है कि सरकार ने सड़क के निर्माण के मामले में अद्भुत कार्य किया है वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये सरकार ने 1661.78 करोड़ का उद्व्यय निर्धारित किया है ।

... क्रमशः ...

टर्न-१६कृष्ण/१२.०३.२०१२

श्री मोतीलाल प्रसाद (क्रमशः) : जो चालू वित्तीय वर्ष २०११-१२ में २५ प्रतिशत ज्यादा है और अगर तुलना वित्तीय वर्ष २००५-०६ से करें तो लगभग ५ गुणा ज्यादा है तो सभापति जी, इस बात से यह समझा जा सकता है कि सरकार की तत्परता सड़कों के प्रति कितनी गहरी है ? जिस प्रकार शरीर के संरचना में नसों की भूमिका होती है उसी तरह की भूमिका राज्य और समाज के विकास के लिये सड़कों की होती है । सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि हमारे राज्य का कोई भाग जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव तथा टोला सड़कों से वंचित न रहे ।

सभापति जी, जहां तक बजट में विभिन्न योजनाओं के लिये प्रबंध किया गया है, उस में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये ६००करोड़ रूपये का प्रबंध किया गया है, जिस से १२५०कि०मी०सड़क का निर्माण होना निर्धारित है । उसी तरह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये ३९१.१५ करोड़ रूपये का प्रबंध किया गया है, जिस से ५५० कि०मी० सड़क निर्माण करने का लक्ष्य है । नाबार्ड संपोषित राज्य योजनान्तर्गत २८२.५४ करोड़ रूपया जिससे ४५५० मीटर लंबाई की अनेक पुलों का निर्माण किया जाना है । विशेष अंगीभूत योजना, जो दलित बस्तियों के लिये हैं, ५००कि०मी०सड़क बनाने के लिये २०० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, आप की सरकार, आप के द्वार योजना के अन्तर्गत ६५ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, मुख्य मंत्री अवशेष सड़क योजना के लिये सड़कों का सर्वे किया गया है ३८,१६७ कि०मी०सड़कों का सर्वे किया गया है, जो २०१२-१३ के लिये प्रस्तावित है । उसी तरह प्रधान मंत्री सड़क योजना में आगामी वर्ष के लिये लगभग ५००० करोड़ रूपये प्राप्त होने का आकलन है, जिस के एवज में १३५० कि०मी० सड़क बनने हैं । इस के अलावे अन्य कई योजनायें हैं, जिस से ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा,जैसे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास से भी कुछ गली सड़कें बनेगी तथा इसी तरह और भी योजनायें हैं, जिस से सड़कों का निमार्ण होना है । महोदय, अपने इसी राज्य में एक समय था, जब अधिकाशं गांवों में, टोलों में कोई व्यक्ति रिक्शा, टेम्पो, अन्य सवारी से गांव, टोलों में नहीं जा पाते थे, पैर से चप्पल, जूता निकाल कर जाते थे । ग्रामीण सड़कों पर कोई सवारी नजर नहीं आती थी । परन्तु समय का दौर बदला है, और अब चमचमाते हुये टेम्पों या अन्य वाहन सड़कों पर दौड़ते हुयें नजर आते हैं । किसी भी समय गाड़ी उपलब्ध है । यह परिवर्त्तन तेजी से बन रहे सड़कों के कारण ही हुआ है । आज हम जिधर से भी जाते हैं, आवागमन की सुविधा मिलाती है । सड़कों के निर्माण से यातायात, आवागमन की सुविधा ही केवल उपलब्ध नहीं हुयी है बल्कि सड़कों के निर्माण से गांवों की सूरत बदल गयी है । सड़कों के निर्माण से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं कृषि में गुणात्मक अंतर आया है । गांवों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है । लोगों में व्यवस्था के प्रति एक विश्वास भाव जगा है । अब लोक निराशा की बात नहीं करते है, कोई शिकायत भी करता है तो उस में अपेक्षा होती है कि इसका

..

निराकरण हो जायेगा । कृषि पैदावार अथवा शब्जियों का वाजिब कीमत अब किसानों को मिलने लगा है । सड़कों के कारण अब व्यापारी गांवों में आने लगे हैं, गांवों के लोगों को भी बाजार की गतिविधियों की जानकारी मिलने लगी है । अपने कृषि उत्पादों को बड़े सहज और आसानी से बाजारों में पहुंचा कर अच्छे कीमत पाने लगे हैं, सभापति जी, मेरे क्षेत्र में एक सड़क है, ग्रामीण कार्य विभाग का जो सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया से पूर्वी चम्पारण से भंडार चौक तक सड़क जाती है, लगभग १५ कि०मी० लम्बाई का सड़क है, परन्तु लाल बखिया नदी पर पुल नहीं होने के कारण बाढ़-बरसात में मार्ग बाधित हो जाता है, नदी के दोनों तरफ पक्की सड़क बनी हुयी है मेरा आग्रह होगा कि उक्त रास्ते में लाल बखिया नदी के जमुआ घाट पर पुल का निर्माण करा दिया जाय ताकि उस इलाके के एक बड़ी आबादी को आवागमन की सुविधा मिल जायेगी । महोदय, मुख्य मंत्री के पहल पर ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक ४८६ दिनांक १४.०६.२०११ के एवज में कार्यपालक अभियंता सीतामढ़ी ने १५ करोड़ की लागत का एक प्रपोजल दिनांक २०.०७.२०११ को पत्रांक ५७५ भेजा है, जो विभाग में लंबित है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष २०१२-१३ की योजना में शामिल कर लें । अभी विपक्ष के माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार राय जी जो कटौती का प्रस्ताव लायें हैं और उस प्रस्ताव में उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता का सवाल खड़ा किया है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं सभापति जी कहना चाहूंगा कि विभाग ने बहुत ही पारदर्शी और अच्छी व्यवस्था कायम की है, २५लाख से ऊपर की जितनी भी योजनायें विभाग क्रियान्वित कर रही है, उन सभी में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की है, इसके साथ ही, ऑन लाईन अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी है, सभी इन्जीनियरों, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता का डिजिटल सिगनेचर बनाया गया है, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार रूलर रोड डेवलपमेंट, बी०आर०आर०डी०ए० के द्वारा सभी कार्यों का कार्यान्वयन हो रहा है जो सोसाईटी एक्ट,१८६० के तहत निबंधित है । सभापति जी, गुणवत्ता के सवाल पर सरकार संवेदनशील है, विभाग कार्रवाई कर रहा है । आप ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिये सभापति जी, आप के प्रति आभार प्रकट करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

...

श्री उमाकांत यादव : सभापति महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय सभापति महोदय, जैसाकि हम जानते हैं, यह बजट वर्तमान सरकार का आठवां वार्षिक बजट है, जिसमें संसदीय प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार के द्वारा सदन में बजट पेश किया गया है और उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप आज हम इस बजट पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुये हैं ।

महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण का जो किताब है

उसके अनुसार,वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के बजट से यह ज्ञात हो रहा है, उस में ग्रामीण कार्य विभाग को वर्ष २०११-१२ में १२००करोड़ रूपया सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिये दिया गया था, वहीं २०१२-१३ में १६६१.७८करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है अर्थात ४६१ करोड़ रूपये अधिक दिये गये हैं ।

महोदय, जैसाकि ज्ञात है, बिहार में तीन प्रकार की सड़कें मुख्यतया बनती हैं :- एक पी०डब्ल्यू०डी० के द्वारा, दूसरा सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा और तीसरा सड़क, जिला स्तर पर बनाये जाते हैं । ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो सड़कें कभी बनाया जाते थे, वह सब अब बिल्कुल मृतप्राय है । ग्रामीण सड़कों की संपूर्ण जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग के ऊपर ही है और यही बनाती है । माननीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि सड़क किसी भी राज्य का दर्पण होता है । सड़कों का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर, आर्थिक विकास पर पड़ता है । जब कभी बाहर से हमारे अतिथि आते हैं और पर्यटक आते हैं तो सड़क और यहां की विधि-व्यवस्था निश्चित रूप से उन को प्रभावित करता है । इसलिए कोई भी सरकार सड़क और विधि-व्यवस्था को प्रथम प्राथमिकता में रखकर उस पर कार्य करती है । महोदय, सरकार कह रही है कि अभी प्रधान मंत्री सड़क का नेट वर्किंग कर रहे है, प्रधान मंत्री सड़क का नेट वर्किंग उस सड़क में नहीं किया जा रहा है, जो कभी कालीकृत था या कभी लिंक से जुड़ा हुआ था ।

क्रमशः :

बहुत कुछ अपनी नजरों से देखे होंगे। उस जिला की जो स्थिति है, इस तीसरे यात्रा में सड़कों के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी विद्यापति धाम एवं विशाल बलिराजगढ़ का भी उन्होंने यात्रा किया, उस समय ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति थी उसको उन्होंने अपने नजर से भी देखा होगा और हमारे माननीय डॉ0 भीम सिंह जी ग्रामीण कार्य मंत्री तो उस जिला के प्रभारी हैं भी वो भी देखते होंगे परन्तु विकास का जो रफ्तार होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा जो बहुत सारी आबादी जब हम गत विधान-सभा में चुनाव जीतकर आये थे तो हमने पहला प्रश्न किया था सुफी से लेकर बाबूबरही तक तीन प्रखंड को जोड़ता है,बाबू बरही भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है, उस समय मंत्री जी का भी जवाब हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे कि निधि की उपलब्धता पर इस सड़क की प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा जो बहुत सारी आबादी का जो गांव है जैसे सुखी से बाबूबरही,बरूआर,ढोरी,तिरहुता, ढलोज,धर्मबोर,बलाही जितनी बड़ी बड़ी आबादी का गांव है उस आबादी को प्रधानमंत्री नेटवर्किंग के नाम पर छोड़ा जा रहा है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इस गांव से लोगों को घर से निकलने का रास्ता भी कहीं नहीं है, लोग निकल नहीं पाते हैं। मैं अपने स्तर से जिला पदाधिकारी से लेकर के माननीय प्रभारी मंत्री जी से आग्रह किया कि एक बार हमको ऐसा मौका मिले जो हमारे क्षेत्र में प्रोग्राम हो,मन में था कि उनको हम स्थिति से रू ब रू करायेंगे लेकिन ऐसा सौभाग्य हमको नहीं मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से भी दावे के साथ कहना चाहूंगा,निश्चित तौर पर इस सरकार की भावना थी कि हम विकास करें लेकिन ग्रामीण सड़क के नाम पर इस बार के बजट में 461 करोड़ रू0 दिया गया। जितनी बड़ी आबादी बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों की है, उस आबादी के मुताबिक ये 461 करोड़ रू0 ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन की तरह है इससे कितना विकास हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार किसी दल का सरकार नहीं होता माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दल के मुख्यमंत्री नहीं होते, पूरे राज्य के होते हैं, बिहार के होते हैं, उनको सारे जगह एकरूपता रहनी चाहिए। मुझे आपके माध्यम से सभापति महोदय,कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि हमलोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। सूचना के अधिकार के तहत हम मांग भी रहे हैं, मांगे भी हैं, हमको उपलब्ध नहीं हुआ है लेकिन मैं 2-4 दिन के बारे में आपको कहना चाहूंगा जो अभी सरकार के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जिस जिस तरह का सड़क बनता है, उसमें है मुख्यमंत्री सड़क योजना,मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना,न्यूनतम आवश्यता कार्यक्रम,नबार्ड सम्पोषित रूलर

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के सहारे आपकी सरकार आपके द्वार इसमें सिड्यूल कास्ट कम्पोनेंट आपदा के लिए सोल्टर और डिजैस्टर सेंटर, बोर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और विश्व बैंक प्रोग्राम, मैं आपको कहना चाहूंगा एम0आर0 के द्वारा जो पुरानी सड़क का मरम्मत किया जाता है, उस सड़कों में मधुबनी जिला में एकरूपता देखने को नहीं मिला है। अभी विश्व बैंक के द्वारा सड़क का जो चयन किया गया है उसमें भी एकरूपता नहीं है। मैं सरकार को आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, माननीय ग्रामीण कार्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार किसी दल का नहीं होता है, सरकार पूरे बिहार का होता है जिस तरह बिहार जबतक नहीं बढ़ेगा, तबतक भारत नहीं विकसित हो सकता है उसी तरह जबतक मधुबनी जिला बाबूबरही विधान-सभा क्षेत्र विकसित नहीं होगा तबतक बिहार कतई विकसित नहीं हो सकता है। सभापति महोदय,इसी सदन में माननीय सदस्य ने कभी कहा था जो तिजोरी से पैसे की लूट हो रही है लेकिन अभी तो सड़क पर पैसे की लूट हो रही है। तिजोरी की बात कहां तक सही है, कहां तक सही नहीं है, यह तो अतीत की बात है, उसका सत्ता भी हस्तांतरण हो चुका है लेकिन सड़क की नई तकनीक से जो लूट शुरू हुआ है, लूटा जा रहा है यह सम्पूर्ण बिहार में लोग जानता है कि स्टीमेट घोटाला के माध्यम से जितना लूट हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा रोड बनता है एन0एच0ए0आई0 फोर लेन जो बनता है। भारत सरकार के द्वारा उसको सबसे अच्छा सड़क कहा जाता है। इसके अलावा एन0एच0 भारत सरकार की जो सड़क है उस सड़क को माना जाता है, उसके अलावा एस0एच0 की सड़क बनती है जो राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत सड़क बनती है, उसके बाद मेजर डिस्ट्रीक्ट बोर्ड की सड़क है, आर0ई0ओ0 की सड़क है, ग्रामीण सड़के हैं लेकिन जो सभापति महोदय.एन0एच. की सड़क पर या एन0एच0ए0आई0 की सड़क पर जितना लोड रहता है, ग्रामीण सड़कों पर निश्चित रूप से उतना लोड नहीं रहता है। मैं स्टीमेट के संबंध में एक दो चीज कहना चाहूंगा जो सड़क जहां बनता है, एन0एच0 और एन0एच0ए0आई0 की सड़कों पर जितना लोड रहता है, उतना ग्रामीण सड़कों पर नहीं रहता है, इसके वाबजूद भी रोड टूट रहा है। मैं एक पुल का उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे मधुबनी जिला में कोतवाली चौक से सरसपाही रोड में एक पुल बना है, उस पुल का लागत होना चाहिए 20-25 लाख (क्रमशः)

टर्न-18/12.3.2012/बिपिन

श्री उमाकांत यादव : क्रमशः जबकि उस पुला का इस्टिमेट करोड़ों में आया है । पिछले लोक सभा चुनाव के वर्ष की बात मैं कह रहा हूं । हमारे यहां एक पुल का मांग हुआ था । उसमें तत्कालीन इंजीनियर जो इस्टिमेट बनाए थे, 60लाख या 70लाख का इस्टिमेट था । आज उस सड़क का इस्टिमेट जा रहा है पौने तीन करोड़ पर, दो करोड़ बावन लाख का है ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस्टिमेट घोटाले की जो यह स्थिति है, इस पर सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय ग्रामीण मंत्री जी भी, दोनों इंजीनियर भी हैं, कर्मठ भी हैं, और चाहते भी हैं कि बिहार का विकास हो, लेकिन एक जो मैसेज जा रहा है, यह मैसेज बहुत ही खराब है और इस मैसेज से लोगों को लगता है कि इस्टिमेट घोटाला हो रहा है । कहीं भी रोड की गुणवत्ता नहीं है । हमलोग भी, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने भी सदस्य हैं, उसमें 1974आन्दोलन के भी अधिक सदस्य हैं, हमलोग भी उसी आन्दोलन से आए हैं । हॉं, यह बात इतर है कि इस सदन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे नेता तब भी थे, आज भी नेता हैं, हमलोग कार्यकर्त्ता के रूप में जिला से उनको सहयोग करते थे । मुझे याद पड़ रहा है, जिस टाइम में 1974 का आन्दोलन चल रहा था, और यहां पर इमर्जेन्सी लगा था, बिहार की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, पिसा रही थी भ्रष्टाचार से और प्रशासन से, उस टाइम में इमर्जेन्सी को सत्य साबित करने के लिए तत्कालीन सरकार ने इमर्जेन्सी को जस्टीफाई करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला साहब को यहां बुलाए थे और अब्दुल्ला साहब के साथ, एक उस समय के पत्रकार महोदय, जनाव शमीम अहमद साहब भी आए थे । इसी पटना में उनका मिटिंग हुआ था और अंजुमन इस्लामिया हॉल में उनकी बैठक हुई थी, जबकि सरकार यह चाहती थी कि इस इमर्जेन्सी को जस्टीफाई करें । लेकिन उसमें एक अब्दुल्ला साहब का बयान आया था- करप्शन कम्स फ्रॉम द टॉप, यह मैं समझता हूं इसमें काफी लॉजिक है और किसी भी सरकार के लिए यह बहुत बड़ी चीज है । सरकार के उपर जितना विश्वास बिहार की आवाम ने किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उपर किया है यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और हमारे डॉ0भीम सिंह जी इंजीनियर भी हैं, विद्वान भी हैं, कर्मठ भी हैं, उनके जिम्में बिहार का ग्रामीण विकास है । जब तक

ग्रामीण विकास नहीं हो पाएगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा । इसमें कमी आ रही है । मैं सरकार को, सरकार पर आरोप लगाता हूं जो आम लोगों के मन में भावना है, जो इस्टिमेट घोटाला हो रहा है और गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है । अंत में इन्हीं बातें के साथ, महोदय, मैं अभी विश्व बैंक के द्वारा जो अभी मधुबनी जिला में सड़क का चयन किया गया है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 15-15, 20-20सड़क का चयन किया गया है, उसको लिया गया है । किसी-किसी विधान सभा में दो ठो है, एक ठो है, चार ठो है, पांच ठो है, इसको क्या समझा जाए । एम0आर0 में जो रूपया दिया गया है, एम0आर0 की स्थिति यह है, मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि एम0आर0 का रूपया कहां जाता है ? एक तो जिस क्षेत्र में आवंटन होता है उसमें भी बहुत का अंतर है । मैं उसका सूचना अधिकार के तहत मांगा हूं । सब योजना का मैं ले रहा हूं । लेकिन जहां बनता भी है उसका तो कोई देखने वाला ही नहीं है । पच्चीस लाख रूपया जाता है, बीस लाख रूपया जाता है, एक सौ फीट भी बनता है कि नहीं बनता है, कोई न देखने वाला है, न सुनने वाला है । पदाधिकारी, इंजीनियर किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । लूट है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा - 2011-12 के बजट में हमारे मधुबनी जिला का कर्णान्कित रूपया था 12करोड़ रूपया, और अनुपूरक के माध्यम से गया फिर चार करोड़ रूपया, सोलह करोड़ रूपया गत् वित्तीय वर्ष में हमारे मधुबनी जिला का कर्णान्कित था । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 25प्रतिशत् रूपया भी खर्च नहीं हो पाया है । यह रूपया क्यों नहीं खर्च हुआ, जब इतने कर्मठ, विद्वान और स्वयं इंजीनियर हमारे विभागीय मंत्री हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जिला के हैं, 20-25प्रतिशत् भी रूपया खर्च नहीं हो पाया । मैं माननीय मंत्री जी से अपने भाषण में भी इस बात को जानना चाहूंगा कि इसका दोष वहां के पदाधिकारी पर है, इंजीनियर पर है कि क्यों नहीं बन पाया ? इतना ही नहीं, मैं अपने विद्वान मंत्रीजी से यह भी उनके बजट भाषण में जानना चाहेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष का जो कर्णान्कित राशि होगा हमारे जिला का, उस जिला में यह जो बकाया है 2011-12 का जो रूपया है वह रूपया एक्स्ट्रा में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

...

माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार की मंशा जो हो, लेकिन उनके पदाधिकारी लोग ढंग से सतह पर काम करना नहीं चाहते हैं और कहने के लिए रोड पर, सड़क पर, एक चीज मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से कि सरकार और हमारे मंत्री जी, सरकार हर समय कहती है कि बिहार की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार न्याय के साथ विकास करती है । माननीय सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि न्याय शब्द इतना विशाल है, मैं समझता हूं जब से मानव की उत्पत्ति हुई, समाज की व्यवस्था हुई, तब से लेकर सारे धर्मशास्त्रों में, इतिहासों में सारे जगहों पर न्याय के आधार पर ही यह सृष्टि टिका हुआ है, समाज टिका हुआ है । न्याय शब्द अपने साथ जोड़े हैं, तो उस न्याय शब्द का न्यायिकपूर्वक उपयोग होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए, जनता के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए । बिहार की जनता जिस रूप में इनको अपना समर्थन दिया है यह ऐतिहासिक ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसमें यदि न्याय नहीं होगा और जो सरकार कहती है कि मैं न्याय के साथ विकास कर रहा हूं तो यह जनता के लिए बहुत गलत होगा । इसलिए मैं सरकार से हर समय आग्रह करूंगा कि अन्याय न करें, न्याय के साथ आप विकास करते हैं तो न्याय शब्द को प्राथमिकता देनी चाहिए । न्याय शब्द कहीं देखने में नहीं मिलता है । जब माननीय विधायक जी के साथ, किसी भी पक्ष के हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, उनके क्षेत्र में जब एकरूपता नहीं है, उन्नीस-बीस होता है तो हो सकता है कि प्राक्कलन के आधार पर होता हो, बारह-बीस का अंतर होता है, पंद्रह-बीस का अंतर होता है, दस-बीस का अतर होता है । आपके इंजीनियर प्राक्कलन बनाते हैं, एक तो प्राक्कलन का कोई ठीक नहीं है, उसमें भी समय पर काम नहीं होता है । काम होता है कि उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है । यह स्थिति है । यह कहां का न्याय है माननीय सभापति महोदय !

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि न्याय के साथ विकास करने वाली यदि यह सरकार अपने को कहती है तो निश्चित रूप से सबों के साथ न्याय होनी चाहिए । मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र है, भारत नेपाल सीमा पर

अवस्थित है, बहुत सारी नदियों से घिरा हुआ है, उस क्षेत्र में आवागमन का रास्ता बिल्कुल नहीं है । मुख्य सड़क यदि चकाचौंध हुआ, आपके माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से, वहां तो ठीक है लेकिन ग्रामीणों की स्थिति यह है कि बरसात में लोग घर से निकल कर कहीं अपने बगल के गांव में भी नहीं जा सकते हैं इलाज कराने के लिए । ग्रामीण सड़कों पर, एक मिनट सभापति महोदय, सुक्खी से लेकर बाबूबरही भाया छोरही-बड़ुआर-तिरहुता, और झरौल से लेकर धयाम्बोर, सहरवा से लेकर बगौल, और मदराहा से लेकर, ऐतिहासिक जगह है, विसौल, राजावलिगढ़, झंझारपुर रेलवे स्टेशन पर वाचस्पतिनगर स्टेशन पर उसका बोर्ड लगा हुआ है, वहां से लोग मंगलाहा तक तो आते हैं, लेकिन मंगलाहा से राजा विशाल वलिराजगढ़ कहां जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है । चार किलोमीटर रोड है । इस रोड को जोड़ कर, वहां का जो ऐतिहासिक भूमि है, वहां का जो अधिक आबादी का गांव है, उनका सम्मान होन चाहिए, सड़क बननी चाहिए । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं ।

श्रीमती रंजू गीता: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2012-13 ग्रामीण कार्य विभाग की जो अनुदान मांग सदन में मांग रखी गई है, मैं उसके पक्ष में अपना विचार रखने के लिए खड़ी हूं ।

महोदय, बिहार की लगभग 70से 80प्रतिशत् जनता ग्रामीण क्षेत्रों में वसर करती है । उन्हें सड़क व विश्वास के सेतु के द्वारा यातायात सुगम व आरामदायक और आनन्दमय यातायात की सुविधा मुहैय्या कराना ही ग्रामीण कार्य विभाग का मुख्य उद्देश्य है ।

महोदय, सड़कें किसी भी राज्य की राज्य की धमनियां होती हैं, यानी कि नसें, जिससे अर्थ-व्यवस्था का रक्त-संचार होता है । वास्तविकता तो यह है महोदय कि सड़कों के महत्व को रेखांकित करने की कोई आवश्यकयता ही नहीं है ... क्रमशः

श्रीमती रंजू गीता : ...क्रमशः... क्योंकि सड़क के अभाव में विकास की कल्पना भी बेमानी है । महोदय, ५-६ वर्ष पूर्व में जो सड़कों की दशा और दिशा थी पूरे बिहार में, उससे सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि सदन के सभी माननीय सदस्य पूर्ण रूपेण परिचित हैं और यहां तक ही नहीं, सड़कों में बने बड़े-बड़े गड्ढ़ों जिसकी चर्चा देश-विदेश के पत्र-पत्रिकाओं में भी हुआ करता था । महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि सड़कों पर जो बने गड्ढे, शहरी इलाके में मेन सड़क का जो खुला मेन-होल, जिससे होने वाली दुर्घटनाएँ, अखबार वालों, पत्र-पत्रिकाओं और मीडिया वालों के लिये रोजमर्रा की शैली बन चुकी थी । यही नहीं, यहां तक कि माननीय उच्च नयायालय को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था कई बार । महोदय, मध्यकालीन भारत के शेरशाह ने भी ग्रैंड-ट्रंक रोड बनाकर बिहार के सड़क के महत्व को समझा था और यहां के उद्यमियों, व्यापारियों, आम-आवाम को सुगम यातायात मुहैया कराया था । मैं बता दूं महोदय, पिछले ५-६ वर्ष जो सरकार थी उन्होंने क्या सड़क की दशा बना रखी थी, उससे होने वाली दुर्घटनाएँ आये-दिन का हिस्सा बना हुआ था । एक ट्रक ड्राइवर का अखबार में खबर छपा था ६-७ वर्ष पूर्व, एक ट्रक ड्राइवर का कहना था कि जब मैं अन्य राज्यों में अपनी गाड़ी चलाता हूं तो कभी-कभी झपकियाँ भी ले लेता हूं और जब गाड़ी बिहार में प्रवेश करता है तो मैं एलर्ट हो जाता हूं और मेरी गाड़ी भी अनबैलेंस होने लगती है क्योंकि सड़क में गड्ढ़ा और गड्ढे में सड़क, हमारे पूर्व के वक्ता ने जो बताया कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है तो ट्रक ड्राइवर कहता था कि जब मैं बिहार में प्रवेश करता हूं तो मैं एलर्ट हो जाता हूं और अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जोर से पकड़ लेता हूं कि अब बिहार आ गया है, यहां कुछ भी हो सकता है । यह मानसिकता थी और इस मानसिकता को बदलने वाले विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया पिछले ५ वर्षों और १-१.५ वर्षों के शासनकाल में, यह भी चमत्कार ही है, महोदय । जब विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता सम्भाली तो उन्हें क्या मिला - खाली खजाना और बिहार की जर्जर सड़कें । लेकिन धन्य हैं वीर सपूत, विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना धैर्य खोये बिना बिहार की सड़कों में जो चमत्कार लाया है, उससे कोई भी आदमी आज अपनी दांतों तले अंगुली दबा लेने के लिये विवश है । महोदय, विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री ने सत्ता सम्भालते हुये जो अपने मन में परिसंकल्पनाएँ ली थीं कि बिहार की सड़कें बिहार की आम-आवाम को राजधानी तक पहुंचने के लिये, बिहार राज्य के किसी भी कोने से राजधानी तक पहुंचने के लिये ५ से ६ घंटा की दूरी तय करनी होगी, वह परिसंकल्पना आज उनकी सिद्ध हो रही है, सिद्ध प्रतीत हो रही है । मैं यह भी बता दूं - मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है । सचमुच में महोदय, विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्थर को पानी बनाने का काम किया है सड़क के मामले में । पूर्ववर्त्ती सरकार ने बिहार की सड़कों को सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाने का जो वादा किया था, मैं माफी चाहते हुये अगला शब्द भी कह ही देती हूं कि सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल के जैसी नहीं लेकिन अभिनेता ओमपुरी के गाल के जैसा जरूर बिहार की सड़कों को बना दिया था, महोदय।

महोदय, मुख्यमंत्री सेतु योजना - भारत देश का पिछड़ा राज्य बिहार और इस पिछड़े बिहार राज्य का पिछड़ा जिला सीतामढ़ी, हमारे जिला में जो पहुंचने का पहुंच पथ था, वह कटौंझा जो सीतामढ़ी जिले का लाईफ-लाईन था, उसका भी शिलान्यास और उद्‌घाटन विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया गया । महोदय, कटौंझा पुल लाईफ-लाईन, जिस जिले का कम्युनिकेशन साल के पांच-छः महीने बाधित हो, उस जिले का विकास कैसे हो सकता है, यह आप और हम सभी समझ सकते हैं । इतना ही नहीं, हमारे सीतामढ़ी जिला में वंशी चाचा ढ़ेंग घाट पर पुल के लिये आत्मदाह किये थे, इसके गवाह सदन के सभी माननीय सदस्य भी हैं और सीतामढ़ी जिला वासी भी हैं । उसका भी शिलान्यास और उद्‌घाटन परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी के कर-कमलों के द्वारा हुआ । सीतामढ़ी जिले में ही नहीं, पूरे बिहार में किसी भी वंशी चाचा को आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है पुल बनवाने के लिये, सिर्फ और सिर्फ एक आवेदन लिखिये कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में एक पुल बनवाना है, मुख्यमंत्री सेतु योजना से एक पुल बनवाना है और वह पुल बन जाता है । आज से नहीं महोदय, पाषाण काल और पाषाण युग में भी राजा अपनी प्रजा के बीच में सादे लिबास में घुमा करते थे, ठीक उसी तरह विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री चाहे वह जेठ की लहलहाती दोपहरिया हो, लहलहाती दोपहरिया की धूप हो, चाहे वह पौष या माघ की शीतलहरी हो, हमारे विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री अपनी जनता के बीच में, जनता के लिये, जनता के सेवक बनकर उनकी सेवा, जो उनके द्वारा योजनाएँ बनायी गयी हैं, उनसे जनता लाभान्वित हो रही हैं या नहीं, उनकी सुध-बुध लेने के लिये पहुंचते हैं ।

महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो पूरे बिहार में सड़क का चमत्कार हुआ, वह विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है । इस योजना से गरीब, महिलाएँ, स्वास्थ्य, चिकित्सा, छात्र-छात्राओं को तो सुविधा मिल ही रही है, मुहैया हो रही है, इसके साथ-साथ व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग, छोटे से छोटे गांव में जो हमारे किसान रह रहे हैं, अपने जीवन सिर्फ और सिर्फ किसान अपनी खेती पर बसर कर रहे हैं, उन्हें भी काफी लाभ मिल रहा है । महोदय, आज गांव का एक छोटा सा छोटा किसान जो अपनी खेत या अपनी बाड़ी में भी एक टोकड़ी सब्जी उपजाता है और वह सब्जी सड़क के अभाव में पहले उसको औने-पौने भाव में उसी गांव में बेच देना पड़ता था लेकिन आज जब सड़क बन गया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ग्रामीण इलाकों में जब सड़क बन गया है तो वह पास के शहर में जाकर एक टोकड़ी सब्जी भी बेचकर उससे पहले से दुगुणा मूल्य प्राप्त करता है, जिससे आज छोटे ग्राम में रहने वाले छोटे किसान की भी आर्थिक स्थिति सुधर रही है । यह भी एक जीता-जागता सबूत है और यह महसूस करने की चीज है कि आज विकास विश्वास के साथ, न्याय के साथ हो रहा है, विरोधी दल के नेता जो कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होना चाहिये, वह हो रहा है लेकिन वे कहने से हिचकते रहते हैं, पता नहीं क्या कारण है ।

मैं तो कहती हूं, मैं दर्शन-शास्त्र की छात्रा रही हूं, कहा गया है कि Man is mortal, therefore, all men are mortal. मैं विरोधी पक्ष के लोगों को कहना चाहती

हूं - जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है । इसी तरह विरोधी पक्ष के लोग विवेकहीन हो गये हैं तभी उनको यह चमचमाती सड़कें नजर नहीं आ रही हैं और ये सड़क के महत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं । महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपकी सरकार आपके द्वार योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंगीभूत योजना, आर०आई०डी०एफ० अन्तर्गत नाबार्ड ऋण सम्पोषित राज्य योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - महोदय, मैं पी०एम०जी०एस०वाइ० सड़क की बात कहूं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बाजपट्टी के बारे में कहना चाहती हूं कि वहां तीन प्रखंड हैं, उसके अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० की सड़कें जो उनकी एजेन्सी एन०एच०पी०सी० है, दर्जनों से ऊपर सड़कें आज तीन-चार साल पहले टेन्डर हो गया था, उसका काम आज भी आधा-अधूरा पड़ा हुआ है । ...क्रमशः...

श्रीमती रंजूगीता : (क्रमशः) मैं ऊँगली पर गिना सकती हूँ । महोदय, उसके बाद धरमपुर से खरका वसंत होते हुए धरमपुर, उसके बाद औराई,बोखरा होते हुए जाले पथ, उसके बाद शहिद रामफल मंडल की जन्मभूमि मदिरापुर, मदिरापुर से महम्मदपुर होते हुए पचरा निवाही मुख्य सड़क में मिलती है महोदय । उसके बाद कुम्बा-वाजपट्टी पथ ....

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती रंजूगीता : सभापति महोदय, एक मिनट में महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ । महोदय, जो जिला सड़के ३.५ से लेकर ३.५० तक बनायी जा रही है महोदय, उसे बढ़ाकर के ५.५० से लेकर ७.०० मीटर तक बढ़ानी चाहिए महोदय क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यातायात की सुविधा मुहैय्या हो और दूसरा सुझाव महोदय, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो सड़कें बनायी जाती है, उसका उच्चीकरण होना आवश्यक है महोदय । चूँकि बाढ़ की विभीषिका के दिनों में वहां यातायात बाधित न हो ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती रंजूगीता : आपने मुझे समय दिया महोदय, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ महोदय ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह जी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा २०१२-१३ वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किये जाने वाली राशि की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, सड़क का नाम लेते ही सदन की संख्या याद आती है । जब सड़क की चर्चा प्रारंभ होती है तो बिहार का बदलता स्वरूप दिखने लगता है । सड़क की चर्चा होती है तो बिहार की तकदीर लिखने की कहानी शुरू हो जाती है । महोदय, इस सदन की संख्या जो सत्तापक्ष का है इस बार, उसके यहां पहुंचने तक का कोई मार्ग है तो आधारभूत संरचनाओं के विकास में जो एन०डी०ए० सरकार-१ का पहल है, उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । महोदय, इसीलिए लगता है कि माननीय विपक्ष के सदस्यों को बड़ी चीढ़ होती है सड़क के नाम पर क्योंकि इनकी घटती हुई संख्या का कारण अगर कुछ दिखता है तो ग्रामीण सडक दिख रहा है । ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाये जा रहे तेज गति से सड़कों के निर्माण से पथ निर्माण विभाग की जब चर्चा शुरू होती है तब तो उनका कलेजा फटने लगता है । महोदय, भारत का प्राचिन इतिहास भी सड़कों के साथ प्रारंभ होता है । महाभारत काल के जब चर्चा हमलोग करते हैं तो उस समय भी अनेकानेक पथों की चर्चा का वर्णन आया है । अथर्ववेद में सड़कों की बात आयी है अर्थात् मानव सभ्यता के विकास के साथ सड़क की आवश्यकता प्रारंभ हो गई । पगडंडी से लेकर आज सड़क तक राजमार्ग तक यह देश पहुंचा है, यह बिहार पहुंचा है । महोदय, माननीय विपक्ष के लोगों का आरोप होता है कि शायद बिहार में सड़क का निर्माण केवल केन्द्र सरकार के पैसों से हो रहा है और यही प्रोपगंडा करके आज इनकी यह हालात हुई है क्योंकि बिहार की जनता लोकतंत्र में

इतना भरोसा रखती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इन्हें बताने का काम किया है कि बिहार सरकार अगर भारत सरकार ने निर्णय लिया तो उस समय भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और आज बिहार के नेतृत्वकर्त्ता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी उस सरकार में मंत्री थे । महोदय, उसी समय प्रधानमंत्री सड़क प्रारंभ हुआ था एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए कनेक्टवीटी दी गई थी और उस समय १ रू० डिजल/पेट्रोलियम पर शेष लगाकर इन सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ । ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर का निर्माण प्रारंभ हुआ, सड़कों का इतिहास लिखा गया । भारतवर्ष के अन्दर शेरशाह शूरी ग्रेंड ट्रंक रोड बनाने, जी०टी० रोड बनाने के कारण अगर आज तक विख्यात है । भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण तक अपने पूरे जीवन-काल में यात्रा की है, भगवान श्रीकृष्ण ने पूरब से पश्चिम तक की यात्रा की है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह स्वर्णिम काल भारत के इतिहास का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, जिन्होंने चतुर्दिक सड़क बनाकर, ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर बनाकर सड़क के इतिहास को रच दिया, यह मार्गदर्शन हमें मिला है । उस मार्गदर्शन के आधार पर इस बिहार के अन्दर जब हमने प्राथमिकता के तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्रीगण जब प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण की बात प्रारंभ किये तो यहां की जनता को लगा कि हमारे दुःखदर्द में शामिल होने वाली कोई सरकार वर्षों बाद इस बिहार के अन्दर आयी है और इसलिए एन०डी०ए० के दूसरे शासन के समय अपार बहुमत से जनता यहां भेजी क्योंकि उनकी अपेक्षायें और अधिक थी । सड़क निर्माण का क्षेत्र इतना व्यापक है कि जैसे-जैसे नगर का विकास होता है, जैसे-जैसे गांव का विकास होता है, जैसे-जैसे मुहल्ले का विकास होता है, वैसे-वैसे सड़कों की आवश्यकता बढ़ती जाती है । अगर १५०००कि०मी० प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हुआ है तो उसमें भी हमारा मैचिंग ग्रांट पहले जमा हो जाता है, केन्द्र सरकार के रूपये बाद में आते हैं तो केवल हमने उसी में मैचिंग ग्रान्ट देकर सड़क निर्माण के काम को नहीं रोका । हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योजना के नाम से मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम से योजना चलाकर बिहार को सड़कों से आच्छादित करने का काम किया, कहा कि अगर एक हजार से ऊपर वाला गांव सड़क से जुड़ेगा तो ५०० की आबादी से लेकर १००० तक की आबादी वाला गांव भी सड़कविहिन इस बिहार के अन्दर नहीं रहेगा और जब उस लक्ष्य को महोदय, हम पूरा करने जा रहे हैं तो हम २५० से लेकर ५०० तक की आबादी वाले गांव और मुहल्ले को भी सड़क से आच्छादित करने का निर्णय लिया है, सड़क निर्माण कराने का निर्णय लिया है । हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण यह हो सका है । जब हम पथरीली और कंकरीली सड़क के इतिहास में जाते हैं तो रामायण-काल याद आता है । रामायण में वर्णित है कि भरत जी जब राम से मिलने के लिए चले थे तो उस समय के इंजीनियरों ने उस समय पथरीली सड़क पर किस प्रकार से निर्माण कार्य हो सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों का समतलीकरण करके वृक्षों को हटाकर, लता-गुलमों को हटाकर

सड़कों का निर्माण करके भरत राम का मिलन कराया था, सड़क का यह इतिहास है महोदय । सड़क हमारे सांस्कृतिक विरासत को बताता है, सड़क भारत के शाश्वत सनातन चिन्तन को दर्शाता है, सड़क केवल सड़क नहीं होता है महोदय, यातायात के कई साधनों में सड़क सबसे महत्वपूर्ण है । सबसे पहले जल-मार्ग को सुलभ माना लोगों ने लेकिन बन्दरगाह से बन्दरगाह तक जाने के लिए, बन्दरगाह से नगरों तक जाने के लिए जब सड़कों की आवश्यकता पड़ी तो सड़क का निर्माण अबाध गति से इस देश के अन्दर प्रारंभ हुआ । एक उत्तर मार्ग होता था, एक पश्चिम मार्ग होता था जो काफी पुराना इतिहास है, जिसे नौरदर्न सड़क के नाम से यूनानियों ने बताया है । इसलिए यह उत्तर भारत का बिहार अतीत ऐसा नहीं था कि जो १५ वर्षों के अन्दर इन लोगों ने दर्शाया है ।

.... क्रमशः ....

....क्रमशः...

श्री अरूण शंकर प्रसाद : हमारा अतीत भी मजबूत था और वर्त्तमान भी हमारा काफी तेजी से मजबूत हो रहा है और बिहार आज तरक्की की शिखर पर जा रहा है । इसलिए मैं माननीय अपने विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि केवल यहीं तक हम नहीं रूक रहे हैं, हमने कृषि रोड मैप में भी सड़क को शामिल किया है । महोदय, याद आ रहा है आपकी बात, जिस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उठकर खड़े हो गये थे, ग्लोबल सबमिट में किसानों के हित की बात मौर्या होटल से करना बंद करो, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ । मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि किसानों की बात यह सरकार पांचसितारा होटल से करेगी, इसके लिए आपको ईर्ष्या होती है तो आपको और ईर्ष्या अगर होगी तो कल आप और कम संख्या में आयेंगे । जब किसानों की बात मौर्या होटल से होनी प्रारम्भ हुई तो क्या किसान केवल खेत में नंगे पांव काम करने के लिए है, चिलचिलाती धूप में हल चलने के लिए है, क्या उसकी बात, और उसके विषय मौर्या होटल से चर्चा न हो, ग्लोबल सबमिट का विषय नहीं बने । किसान इस देश की रीढ़ है और इसलिए किसानों के लिए जितना सड़क निर्माण की जरूरत होगी,

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : उस जरूरत को पूरा करने के लिए कृषि रोड मैप के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग उस काम को भी पूरा करेगी ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें, समय हो गया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय सदस्य उमाकांत बाबू कह रहे थे, वे मेरे जिले के हैं, असत्य कम बोलते हैं और हमारे माननीय विद्वान प्रतिपक्ष के नेता असत्य बोलने के लिए उकसा रहे थे लेकिन सत्य निकल जा रहा था कि इस सरकार की मंशा साफ है । कुछ अधिकारियों से हो सकता है, आज नहीं, प्रारंभिक दिनों से हुआ है । जो कार्य करेंगे, उन्हीं के कार्य में अकुशलता भी दिखेगी और कुशलता भी दिखेगी । लेकिंन हर हमेशा बिहार के पदाधिकारी जिनको आपने लालटेन युग में काम कराया था, आज वे इस बिजली में आकर उनकी गति ऐसी बढ़ी है कि वही अधिकारी जो आपके समय, आप याद कर लीजिए वर्ष २००४ में एक वर्ष के अन्दर चार किलोमीटर भी सड़क नहीं बना पाते थे, आज उन्हीं अधिकारियों के मदद से ३०.७७ किलोमीटर अर्थात् लगभग ३१ किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है । आप चार किलोमीटर प्रति वर्ष कर रहे थे और आज यह प्रतिदिन हो रहा है । यह आंकड़ा कोई बिहार सरकार का नहीं है, भारत सरकार भी इसकी पुष्टि करती है । इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ....

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : सभापति, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा । मैं खजौली विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, अनेकों सड़कों का निर्माण हुआ है लेकिन एकाध प्रमुख सड़कें जो अधूरी रह गयी है, मैं उसकी ओर सक्षम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो बासोपटटी

से लेकर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय है, उस प्रखंड को जोड़नेवाली सड़क जो तिलकोर होते हुए बारा होते हुए जयनगर जाती है, केवल १२ किलोमीटर की दूरी है, जिसमें अभी हमें घूमकर १८-२० किलोमीटर जाना पड़ता है, उसके निर्माण के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क छूट गये है और जिस योजना से भी संभव हो, उसका समावेश करने का प्रयास करेंगे । महोदय, मै अंत में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी कटु बातों को भी गंभीरता से सुनने का प्रयत्न किया है, उन माननीय सदस्यों के प्रति अभार प्रकट करते हुए, आप सभी के प्रति अभार प्रकट करते हुए, खजौली की जनता के प्रति अभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने अपनी बात रखने के लायक मुझे यहां तक बनाकर भेजा है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मनीष कुमार : सभापति महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वर्ष २०१२-१३ के लिए लाये गये अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आज जिस तरह से बिहार विकसित हो रहा है और इस विकास की दौर में अगर कोई ग्रामीण कार्य विभाग के बारे में बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि इस विभाग के लिए मेरी तरफ से विश्वासघात होगा । इसलिए विभाग द्वारा लाये गये अनुदान मांग की पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, बिहार का बड़ा ही स्वर्णीम इतिहास रहा है । बिहार हमेशा चर्चा का विषय रहा है, स्वर्णीम इतिहास रहा है, अच्छी कारणों से चर्चा का विषय बना रहा है । जब बिहार का बंटवारा हुआ तो भी यह एक चर्चा का विषय बना रहा । महोदय, जब बिहार और झारखंड राज्य का बंटवारा हुआ, दुर्भाग्यवश सारा खनिज सम्पदा से लदा हमारा राज्य उस समय एकत्रित बिहार था लेकिन दुर्भाग्यवश सारा खनिज संपदा झारखंड राज्य में चला गया और चला जाने के बाद हमारे राज्य में सिर्फ बिहार में एकमात्र चीज बचा था, जो लोग मजाक और हास्यापद रूप से ताना दिया करते थे, वह था लालू और बालू । स्वभाविक है कि हमारी जनता, बिहार की जनता विचलित हो गयी थी, आलू के बारे में बोला जाता था लेकिन उस काल में आलू भी नष्ट हो गया था लेकिन इस राज्य में, इस सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी की कुशल नेतृत्व वाली सरकार मे अब आलू उत्पादन हो रहा है । महोदय, जितनी खनिज सम्पदा थी, सब झारखंड राज्य में चला गया था और बिहार की जनता ब्यथित थी, विचलित थी, उनके सामने में बिल्कुल जीरो था कि अब बिहार क्या करेगा, बिहार किस ओर बढ़ेगा ? सबसे ज्यादा जो चिंतित थे तो बिहार के किसान भाई सबसे ज्यादा चिंतित थे । चूंकि किसान का एकमात्र रोजमर्रा का साधन होता है अनाज उत्पादन करना, अन्न उत्पादन करना और हमलोगों तक पहुंचाना । महोदय, सर्वविदित है कि बिहार एक कृषि प्रधान गरीब राज्य है औ आज कृषि प्रधान पर ही मुख्य रूप से आधारित राज्य है लेकिन दुर्भाग्य था कि जब सड़क ही नहीं था तो हमारे किसान द्वारा उपजाये गये अनाज हम तक कैसे पहुंच पाता और बेचारा अनाज देख-देख करके बिलख जाता था, फलस्वरूप जो अनाज उत्पादन करता

था, उसके एवज में उसे राशि नहीं मिल पाती थी । कहने का तात्पर्य यह है कि जो राशि अनाज उत्पादन में लगाये जाते थे, उसका रिटरनिंग तक नहीं मिल पाता था । उसका एक मूलभूत कारण था सड़क का अभाव । जैसा हम शुरू में ही कहे महोदय कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लोग ज्यादा कृषि पर आधारित हैं, यहां पर बैठे हम सभी लोग कृषि क्षेत्र से आते हैं और कृषि क्षेत्र परिवार से ज्यादा जुटे हुए लोग हैं । महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि किसान भाई जो अनाज उत्पन्न करते थे और एकमात्र जरिया था उनका लागत मूल्य वापस हो सके लेकिन सड़क के अभाव में उनका लागत मूल्य भी वापस नहीं हो पाता था, जिसके कारण कृषक भाई, किसान भाई भी व्यथित हो जाते थे, विचलित हो जाते थे । महोदय, सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक कुशल इंजीनियर है और अपने इंजीनियरिंग का प्रभुत्व दिखाकर, बिहार को कुशल नेतृत्व की बदौलत बिहार को प्रगति की ओर बढ़ा रहे हैं । उसी प्रकार हमारे विभाग के माननीय मंत्री डॉ० भीम सिंह जी भी एक कुशल इंजीनियर के रूप में विभाग को प्रगति की ओर आगे बढ़ा रहे हैं । जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जन-जन के नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की नब्ज पकड़कर बिहार को प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसी प्रकार माननीय डॉ० भीम सिंह जी के बारे में कहना चाहूँगा कि वे एक कुशल इंजीनियर होने के नाते ग्रामीणों की नब्ज पकड़कर ग्रामीण सड़क पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण सड़क का निर्माण कराने में हमेशा अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं और प्रयत्नशील हैं । महोदय, जैसाकि मैंने कहा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बंटवारे के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था ।

(क्रमशः)

श्री मनीष कुमार : ... क्रमशः ...

और जनता हताश हो गयी थी और जब 2005 में जब चुनाव आया और चुनाव के बाद हम हमारे माननीय नीतीश कुमारजी के नेतृत्ववाली सरकार बनी लोगों में आस्था जगी, लोगों में आस जगी कि अब बिहार का कायाकल्प होगा लेकिन जनता बहुत होशियार होती है, जनता का प्रभुत्व होता है, जनता के ही बदौलत हम सबलोग आज इस आसन में उपस्थित हैं । जनता पांच वर्ष तक कठिन इम्तहान लेने का काम किया । पांच वर्ष तक, कोई भी परीक्षा दस दिन, बीस दिन, एक महीना का होता है लेकिन हमलोगों की परीक्षा पांच वर्ष तक की होती है और जनता के पांच वर्ष की परीक्षा के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमारजी के नेतृत्व में सरकार ने 84 प्रतिशत अंक, प्राप्तांक करके यहां पर आज पुनः लम्बी तादाद में उपस्थित होने का काम किया है जिसके बदौलत आज सामने विपक्ष की संख्या सिर्फ 24 की तादाद पर है । महोदय, अभी तीन हैं चूंकि महोदय, हमारे विपक्ष के साथीगण विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं जब भी विकास के बारे में बात होती है तो जब सदन में बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि विरोध में बोलते हैं, हालांकि वे सबलोग दबी आवाज में बोलते हैं मजबूरी हैं उनकी, लेकिन जब बाहर जाते हैं, जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं जब जनता के बीच में बैठते हैं, मुझे विश्वास है, सह्रदय विश्वास है वो भी हमारी सरकार की बड़ाई करते हैं उपलब्धि गिनाते हैं । महोदय, ये सच्चाई है, चूंकि मैं भी बहुत तरह के लोगों के बीच में रहता हूं और लोग बताते हैं कि सरकार प्रगति कर रही है,सरकार की अपनी उपलब्धि है, जो उपलब्धि है वह अनमोल है, अमूल्य है । महोदय, आज सड़क के विषय पर ग्रामीण कार्य के विषय पर मैं बोलने के लिये खड़ा हूं, इधर उधर विचलित न होते हुए मैं सड़क पर ही बोलना चाहूंगा । एक समय था महोदय,जब जनता के माध्यम से हमारे उस समय के विधायकगण, मैं ये स्वर्णिम काल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये 1990 से लेकर 2005 के बीच के कार्यकाल की बात कर रहा हूं, जब कोई प्रतिनिधि शीर्ष नेता के पास जाते थे ..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : समाप्त कीजिये, समय हो गया आपका ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, जब शीर्ष नेता के पास जाते थे, तब बोला जाता था, सड़क की मांग की जाती थी तो उन्हें जानकारी दी जाती थी कि बोलो सड़क चाहिये या पुलिस चाहिये? अगर सड़क बन जायेगा तो पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जायेगी । कौन बेचारा पुलिस के डर से फिर से सड़क मांगे, उल्टे पांव वापस आ जाते थे । आज महोदय, जिस प्रकार से हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमारजी ने न्याय के साथ विकास करने का बीड़ा उठाया है, न्याय का कहने का तात्पर्य है अगर सड़क बनी रहेगी तो न्याय के लिये पुलिस भी उसके दरवाजे पर जाकर जनता को, ग्रामीणों को न्याय दिलाने का काम करेगी इसलिये सड़क निर्माण कराना अति आवश्यक है । महोदय, मैं चंद मिनट में अपनी बातों को खत्म

करूंगा आपके माध्यम से महोदय, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्रीजी का सपना है कि किसी भी क्षेत्र से, बिहार के किसी कोना से इस बिहार की राजधानी पटना में 6 घंटे में पहुंचने का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार ने बीड़ा उठाया है वह सफलीभूत होता दीख रहा है और आज उसी के बदौलत जब शनिवार को हमारे लोग, हमारे साथीगण जब अपने क्षेत्र चले जाते हैं तो सोमवार को सदन पकड़ने के लिये सवेरे 6 बजे चलते हैं और 11 बजे यहां सदन में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ये उपलब्धि है महोदय, हमारे ग्रामीण कार्य विभाग की, सरकार की ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें,समय हो गया ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, कुछ अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोलना चाहूंगा महोदय ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : एक मिनट में समाप्त कीजिये आप ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, हालांकि हमारा क्षेत्र, मैं जिस धौरैया विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, मैं था बोल रहा हूं, अब नहीं है क्योंकि 2005 के पहले, मैं जानता हूं महोदय, हमारे साथी जावेदजी का भी घर हमारे क्षेत्र में ही है लेकिन ये खुद कभी भी सड़क पर नहीं चल पाते थे हमेशा गड्ढा में ही चलने का इन्हें मौका मिला था । ये 2005 के बादवाली सरकार ने इन्हें मौका दिलाया..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब समाप्त करें माननीय सदस्य । माननीय सदस्य,श्री पवन कुमार जायसवालजी । अब आप समाप्त करें । समाप्त करें आप ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, आज वो निर्माणाधीन सड़क के बीच में जो जो पुल पड़ता है, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है खैरा वामदेव सड़क, उसके बीच में दो पुल अचानक टूट जाने के कारण वह सड़क निर्माणाधीन तो है लेकिन जब निर्मित हो जायेगा तो पर भी वह सड़क अपूर्ण रहेगा महोदय । इसलिये मैं विनती करता हूं कि उस समय के एस्टीमेट में नहीं शामिल किया गया था ..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य,श्री पवन कुमार जायसवाल । .. अब आप समाप्त करें । नहीं-नहीं.. समय बहुत कम है, आप समाप्त करें । बैठ जांय आप ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय सभापतिजी,मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये ..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय मंत्रीजी को दे देंगे आप । लिखित दे देंगे आप । चलिये,बोलिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : पांच मिनट में खत्म करिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, हमलोग भारत नेपाल सीमावर्ती ढाका विधान सभा क्षेत्र से आते हैं जो पूर्वी चम्पारण जिले में है और मैं समझता हूं कि एन0डी0ए0 2 की सरकार को जो प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ उसमें सड़कों का जाल बिछाना भी प्रदेश

में बहुत बड़ा कारण है और मैं समझता हूं कि पक्ष हो या विपक्ष बिहार में सड़कों की जो स्थिति है जिसका लाभ सभी लोग हमलोग उठा रहे हैं, इससे सारे लोग परिचित हैं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं पहले मोतिहारी से फुलवरिया जाने के लिये हमलोगों को सोचना पड़ता था, सप्ताह में, महीना में एक बार दो बार जाने में सोचना और समझना पड़ता था, आज की स्थिति यह है कि फुलवरिया से मोतिहारी जाने के लिये हमलोगों को दिन में दो बार, तीन बार भी आना जाना पड़ता है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दीखती है । महोदय, जहां तक ग्रामीण कार्य विभाग का सवाल है, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैंने एक गैर सरकारी संकल्प में माननीय मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया था कि 2011-12 में हो जायेगा, मैंने उनको स्मरण कराया कि मंत्रीजी बाकी है,ठीक कुछ ही दिन बाद मेरे क्षेत्र में सामूहिक शादी का कार्यक्रम था मैं निमंत्रण लेकर मंत्रीजी के यहां गया तो मंत्रीजी बोले कि सबसे पहले आपके क्षेत्र का हम काम करेंगे उसके बाद आपके यहां चलेंगे और मैं मंत्रीजी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं मार्च में, 31 मार्च में अभी भी दस-बीस दिन बाकी है और वो कार्य निविदा प्रक्रिया में चला गया, मंत्रीजी तो मेरे यहां नहीं पहुंच सके इस बात का मुझे दुख है लेकिन ससमय कहे हुए वादा को इन्होंने पूरा कर दिया ये बहुत बड़ी बात है । जहां तक ग्रामीण कार्य विभाग का सवाल है,महोदय, विभागीय सचिव जिला स्तर पर जाकर संवेदकों के साथ बैठ कर बात करते हैं कार्य को पूर्ण कराने के लिये, बेतिया में मोतिहारी में पिछले दिनों बैठक हुई है, संवेदकों के साथ विभाग के सचिव अगर बैठक करते हैं और वो भी जहां सख्ती की जरूरत है सख्ती से, जहां प्रेम की जरूरत है वहां प्रेम से और जहां एफ0आई0आर0 की जरूरत है ग्रामीण कार्य विभाग ने एफ0आई0आर0 करके काम को पूर्ण कराने का काम किया है । प्राक्कलन समिति की बैठक में मैंने पांच सड़क अपने क्षेत्र का लिखाया था, विभागीय सचिव बैठे थे, जो कार्य ठेकेदार बंद कर दिया था, कार्य होना बंद हो गया था और वोट के बाद उस गांव में जाना दुर्लभ हो गया था, लोग कहते थे कि सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, महोदय,मैं विभाग को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री को कि वह कार्य पूरा हो गया, चलने के लायक हो गया, आवागमन के लायक हो गया और आज उस गांव में हमलोग जाते हैं तो लोग कहते हैं चलिये भाई विधायकजी, कम से कम आने जाने का साधन सुदृढ़ हो गया है । महोदय,मैंने ग्रामीण कार्य विभाग का जो वक्तव्य है माननीय मंत्रीजी का मैं उसको पढ़ रहा था, प्रतिदिन 31.77 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना, ये अपने आपमें मायने रखता है और कीर्तिमान स्थापित करता है । पक्ष के माननीय साथी हों या विपक्ष के, सवाल उठता है कि हमलोग 2001 में जिला परिषद का चुनाव जीते थे मोतिहारी से, प्रधानमंत्री सड़क योजना का जब पहली बार चयन शुरू हुआ तो जिला परिषद की बैठक में एक किलोमीटर पथ के निर्माण के लिये माननीय सांसद महोदय से बकझक हो गया हमलोगों को । आज सड़क के लिये हमलोग सुझाव देते हैं चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के और सुझाव देते हैं, जो लिखकर देते हैं, पत्राचार का

करूंगा आपके माध्यम से महोदय, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्रीजी का सपना है कि किसी भी क्षेत्र से, बिहार के किसी कोना से इस बिहार की राजधानी पटना में 6 घंटे में पहुंचने का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार ने बीड़ा उठाया है वह सफलीभूत होता दीख रहा है और आज उसी के बदौलत जब शनिवार को हमारे लोग, हमारे साथीगण जब अपने क्षेत्र चले जाते हैं तो सोमवार को सदन पकड़ने के लिये सवेरे 6 बजे चलते हैं और 11 बजे यहां सदन में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ये उपलब्धि है महोदय, हमारे ग्रामीण कार्य विभाग की, सरकार की ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें,समय हो गया ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, कुछ अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोलना चाहूंगा महोदय ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : एक मिनट में समाप्त कीजिये आप ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, हालांकि हमारा क्षेत्र, मैं जिस धोरैया विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, मैं था बोल रहा हूं, अब नहीं है क्योंकि 2005 के पहले, मैं जानता हूं महोदय, हमारे साथी जावेदजी का भी घर हमारे क्षेत्र में ही है लेकिन ये खुद कभी भी सड़क पर नहीं चल पाते थे हमेशा गड्ढा में ही चलने का इन्हें मौका मिला था । ये 2005 के बादवाली सरकार ने इन्हें मौका दिलाया..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब समाप्त करें माननीय सदस्य । माननीय सदस्य,श्री पवन कुमार जायसवालजी । अब आप समाप्त करें । समाप्त करें आप ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, आज वो निर्माणाधीन सड़क के बीच में जो जो पुल पड़ता है, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है खैरा वामदेव सड़क, उसके बीच में दो पुल अचानक टूट जाने के कारण वह सड़क निर्माणाधीन तो है लेकिन जब निर्मित हो जायेगा तो पर भी वह सड़क अपूर्ण रहेगा महोदय । इसलिये मैं विनती करता हूं कि उस समय के एस्टीमेट में नहीं शामिल किया गया था ..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य,श्री पवन कुमार जायसवाल । .. अब आप समाप्त करें । नहीं-नहीं.. समय बहुत कम है, आप समाप्त करें । बैठ जांय आप ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय सभापतिजी,मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये ..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय मंत्रीजी को दे देंगे आप । लिखित दे देंगे आप । चलिये,बोलिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : पांच मिनट में खत्म करिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, हमलोग भारत नेपाल सीमावर्ती ढाका विधान सभा क्षेत्र से आते हैं जो पूर्वी चम्पारण जिले में है और मैं समझता हूं कि एन0डी0ए0 2 की सरकार को जो प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ उसमें सड़कों का जाल बिछाना भी प्रदेश

में बहुत बड़ा कारण है और मैं समझता हूं कि पक्ष हो या विपक्ष बिहार में सड़कों की जो स्थिति है जिसका लाभ सभी लोग हमलोग उठा रहे हैं, इससे सारे लोग परिचित हैं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं पहले मोतिहारी से फुलवरिया जाने के लिये हमलोगों को सोचना पड़ता था, सप्ताह में, महीना में एक बार दो बार जाने में सोचना और समझना पड़ता था, आज की स्थिति यह है कि फुलवरिया से मोतिहारी जाने के लिये हमलोगों को दिन में दो बार, तीन बार भी आना जाना पड़ता है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दीखती है । महोदय, जहां तक ग्रामीण कार्य विभाग का सवाल है, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैंने एक गैर सरकारी संकल्प में माननीय मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया था कि 2011-12 में हो जायेगा, मैंने उनको स्मरण कराया कि मंत्रीजी बाकी है,ठीक कुछ ही दिन बाद मेरे क्षेत्र में सामूहिक शादी का कार्यक्रम था मैं निमंत्रण लेकर मंत्रीजी के यहां गया तो मंत्रीजी बोले कि सबसे पहले आपके क्षेत्र का हम काम करेंगे उसके बाद आपके यहां चलेंगे और मैं मंत्रीजी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं मार्च में, 31 मार्च में अभी भी दस-बीस दिन बाकी है और वो कार्य निविदा प्रक्रिया में चला गया, मंत्रीजी तो मेरे यहां नहीं पहुंच सके इस बात का मुझे दुख है लेकिन ससमय कहे हुए वादा को इन्होंने पूरा कर दिया ये बहुत बड़ी बात है । जहां तक ग्रामीण कार्य विभाग का सवाल है,महोदय, विभागीय सचिव जिला स्तर पर जाकर संवेदकों के साथ बैठ कर बात करते हैं कार्य को पूर्ण कराने के लिये, बेतिया में मोतिहारी में पिछले दिनों बैठक हुई है, संवेदकों के साथ विभाग के सचिव अगर बैठक करते हैं और वो भी जहां सख्ती की जरूरत है सख्ती से, जहां प्रेम की जरूरत है वहां प्रेम से और जहां एफ0आई0आर0 की जरूरत है ग्रामीण कार्य विभाग ने एफ0आई0आर0 करके काम को पूर्ण कराने का काम किया है । प्राक्कलन समिति की बैठक में मैंने पांच सड़क अपने क्षेत्र का लिखाया था, विभागीय सचिव बैठे थे, जो कार्य ठेकेदार बंद कर दिया था, कार्य होना बंद हो गया था और वोट के बाद उस गांव में जाना दुर्लभ हो गया था, लोग कहते थे कि सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, महोदय,मैं विभाग को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री को कि वह कार्य पूरा हो गया, चलने के लायक हो गया, आवागमन के लायक हो गया और आज उस गांव में हमलोग जाते हैं तो लोग कहते हैं चलिये भाई विधायकजी, कम से कम आने जाने का साधन सुदृढ़ हो गया है । महोदय,मैंने ग्रामीण कार्य विभाग का जो वक्तव्य है माननीय मंत्रीजी का मैं उसको पढ़ रहा था, प्रतिदिन 31.77 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना, ये अपने आपमें मायने रखता है और कीर्तिमान स्थापित करता है । पक्ष के माननीय साथी हों या विपक्ष के, सवाल उठता है कि हमलोग 2001 में जिला परिषद का चुनाव जीते थे मोतिहारी से, प्रधानमंत्री सड़क योजना का जब पहली बार चयन शुरू हुआ तो जिला परिषद की बैठक में एक किलोमीटर पथ के निर्माण के लिये माननीय सांसद महोदय से बकझक हो गया हमलोगों को । आज सड़क के लिये हमलोग सुझाव देते हैं चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के और सुझाव देते हैं, जो लिखकर देते हैं, पत्राचार का

जवाब मिलता है, पथ निर्माण का मामला हो या ग्रामीण कार्य विभाग का मामला हो, सभी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण हो रहा है और कहने में कहीं हिचक नहीं है कि हमलोग जो पथ लिखकर देते हैं वह अगर जनोपयोगी होता है तो हमलोगों से आगे बढ़कर विभाग भी उस काम को क्रियान्वित कराकर अपना यश स्थापित करने में अहम् भूमिका निभाने का काम करता है । महोदय, मैंने विभाग को एक सुझाव दिया था कि ग्रामीण कार्य विभाग का जो पुनर्गठन होने जा रहा था प्रमंडलों का, अंचल का,

... क्रमशः ...

श्री पवन कुमार जायसवाल (क्रमशः) : मैंने एक पत्र दिया था माननीय मंत्री को और विभागीय सचिव को कि पूर्वी चम्पारण में प्रमंडलों का जब पुनर्गठन हो, अंचल का पुनर्गठन हो तो कृपया उस पर ध्यान दिया जाय। इस हिसाब से होगा तो क्षेत्र के बनावट के हिसाब से ठीक होगा। मैंने किताब का अवलोकन किया तो मुझे बेहद खुशी हुयी कि हमलोग माननीय सदस्य के नाते जो सुझाव देते हैं, विभाग अगर उस पर सकारात्मक है, विभाग अगर उस पर अमल करता है तो निश्चित रूप से जनता का वोट, जो हमलोगों को मिला है, लगता है कि उसका सपना, उसका सुझाव हमलोगों का दिया हुआ विचार साकार हो रहा है । मैंने जो सुझाव दिया, जो प्रमंडल का बंटवारा हुआ, जो प्रखंड अगल-बगल में थे, उस को उसी ग्रामीण कार्य प्रमंडल में रखा गया, मोतिहारी पुराना जिला है, हमलोगों का अंचल बेतिया में था, मैंने सुझाव दिया था कि मोतिहारी पुराना जिला है, २७ प्रखंड है, बेतिया १५ प्रखंड है, वहां पर अगर होना हो तो दोनो जगह हो जाये । इस किताब को पढ़ने के बाद मैं बेहद खुश हूं कि बेतिया भी एक अंचल है और मोतिहारी भी एक कार्य अंचल हुआ । ग्रामीण कार्य प्रमंडल के के बंटवारा में, क्षेत्र के पुनर्गठन में, सभी प्रखंडों का ख्याल रखा गया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ग्रामीण कार्य विभाग का जो कार्य है, वह सराहनीय है और माननीय सदस्यों का कद, प्रतिष्ठा और क्षेत्र के मान-सम्मान में ग्रामीण कार्य विभाग का जो काम है, वह सराहनीय है ।

....

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम सभी जानते हैं कि बिहार गांवों में बसता है और गांवों में जो हमारे ग्रामीण हैं, गांवों जो रहनेवाले लोग हैं, अगर वे सुखी-सम्पन्न नहीं होगे तो हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ पायेगा । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, जब तक ग्रामीणों का विकास नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है । हमारे यहां पथों का क्या महत्व है, जहां सड़क नहीं है, उनलोगों से पूछा जाय, जिस गांव में सड़क नहीं है , वह विकास से कट जाता है, वह विकास से कोसों दूर चला जाता है, मुख्य धारा से कट जाता है । शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से सभी तरह से पीछे हो जाते हैं । इसी का ख्याल रखते हुये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, २००५ में जो बजट था और आज का जो बजट है ग्रामीण कार्य विभाग का, आसमान-जमीन का फर्क है । आज वित्तीय वर्ष २०११-१२ में १२०० करोड़ रूपये का बजट था जो अब २५ प्रतिशत बढ़ाकर वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में १६६१.७८करोड़ का कर दिया गया है । हम जानते हैं कि बिहार में सड़कों की क्या स्थिति थी ? वर्ष २००५ के पहले बिहार में सड़कों की स्थिति क्या थी ? आने-जाने में कठिनाईयां हो रही थी, लोग गांव नहीं जा पाते थे, यहां पर्यटक नहीं आ पाते थे,जो बीमार थे, अस्पताल नहीं जा पाते थे, परिवर्त्तन हुये । अदभूत्

परिवर्त्तन हुये । जो लोग सोचे भी नहीं थे कि ये काम होंगे। ऐसे पुल बनेंगे, ऐसे सड़क बनेंगे और वह भी विधायक जी की अनुशंसा पर। आज माननीय विधायक अनुशंसा कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री सेतु के द्वारा, मुख्य मंत्री सड़क के द्वारा आज ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछ रहा है, आज बिहार हाई परफौर्म करने वाला राज्य बन गया है । आज बिहार विकास में अनुकरणीय हो गया है । दूसरे राज्य आत्मसात् कर रहे हैं कि बिहार कैसे तरक्की कर रहा है । आज बिहार को मोडल के रूप में अपनाया जा रहा है और बिहार को दूसरे राज्य के लोग आत्मसात् कर रहे हैं कि बिहार एक अनुकरणीय राज्य हो गया है । आज बिहार में मुख्य मंत्री सडक योजना के तहत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में ६०० करोड़ रूपये खर्च होंगे, जिसमें १२५० कि०मी०सड़क का निर्माण होगा। न्यूनतम आवश्यकता योजना कार्यक्रम के तहत ३९१.१५ करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे जिसमें ५५०कि०मी०रोड का निर्माण होगा। नाबार्ड द्वारा २८२ करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, जिस पर ४५५० मीटर लंबाई का सड़क का निर्माण होगा, पुल का निर्माण होगा। अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंगीभूत योजना के तहत २०० करोड रूपये व्यय किये जायेंगे, जिस से ५००कि०मी० सड़क का निर्माण किया जायेगा। आप की सड़क आपके द्वारा योजना के तहत ६५करोड़ की राशि खर्च किये जाने का प्रावधान है, जिसमें १२५ कि०मी०सड़क का निर्माण किया जायेगा। इसलिए महोदय, विकास बताने की चीज नहीं है, विकास महसूस करने की चीज है । विकास को देखने की चीज है । विकास को महसूस किया जाता है और समाज का अंतिम व्यक्ति बिहार में महसूस कर रहा है कि बिहार में क्या परिवर्त्तन हो रहे हैं । भले कोई बोल दें, विपक्ष में बोल दें कि बाहर में कुछ नहीं दिख रहा है, राजनीतिक कारणों के कारण, लेकिन जब वे अकेले में बैठते हैं, जब अपने लोगों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं कि जरूर बिहार में विकास हो रहा है, बिहार उन्नति कर रहा है और आज दुनियां की नजर इस पर है । कई राज्य और देश के के लोग यहां से अपने नेता को बुलाते हैं कि बिहार में आपने कौन-सा परिवर्त्तन किया, कौन-सी नीति अपनायी ताकि हमारे राज्य का भी हमारे देश का भी कायाकल्प हो, उत्थान हो । आज मुख्य मंत्री सड़क योजना चल रही है, मुख्य मंत्री सेतु योजना चल रही है, महोदय, जहां लोग जा नहीं पाते थे, छोटे-छोटे पुलिया के कारण, बड़े-बड़े पुल के कारण आवागमन अवरूद्ध था, वहां पर पुल के निर्माण हो रहे हैं । वहां पर पुलियों के निर्माण हो रहे हैं, लोग आ-जा रहे हैं, लोगों का अवागमन सुलभ हो गये हैं, पहले एक किलो मीटर चलने में घंटो लग जाते थे, अब हमारे माननीय मंत्री जी का जो संकल्प है, राज्य के किसी कोने से पटना आने में मात्र ६ घंटे लगेंगे और उसी के रफ्तार से हमारे यहां रोड का निर्माण भी हो रहा है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, बिहार के काने-कोने से वाकिफ हैं, भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं और उसी को ध्यान में रखकर नीतियां बन रही हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, एक अच्छा माहौल बना है, विकास के लिये एक अच्छा माहौल भी होना आवश्यक है । एक खुशनुमा माहौल बना है ।

कोई भी संवेदक कहीं जा कर काम कर सकता है । भय का माहौल नहीं है । किसी पर रोक नही है । लोग स्वच्छ माहौल में काम कर रहे हैं । आज तरक्की हो रही है और हमारा जो बिहार था, उसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है । आज बिहार नीतीश कुमार के नाम से जाना जा रहा है। आज बिहार पिछड़ेपन के नाम से नहीं जाना जा रहा है । आज हांसिये पर नहीं है, आज बिहार को जाना जा रहा है विकास के नाम पर । बिहार को जाना जा रहा है तरक्की के नाम पर । आज हमारे यहां कृषि रोड मैप का निर्माण किया गया है, तैयारी चल रही है जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग भी एक विभाग है । उसकी अहम भूमिका है । कृषि का उत्पादन होता है, किसान उत्पादन करते हैं और उनके उत्पादन का कहीं उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। जब रोड का निर्माण होगा, जब सडकों का निर्माण होगा, तो उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। रोगी जल्द से जल्द स्वास्थ्य केन्द्रों में आयेंगे, अस्पताल में आयेंगे, उनको लाभ होगा, उनका इलाज करने में उचित सहायता एवं सहयोग मिलेगा। आज जो हमारा संकल्प है, कि २०१७ तक २५० जो आबादी है, जिस गांव की बसावट है, वहां भी सड़क का निर्माण होगा, जिसके तहत ३८,१६७कि०मी० निश्चित रूप से सड़क का निर्माण होना निश्चित हुआ है । प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे यहां पिछड़ा हुआ है, केन्द्र सरकार की दोहरी नीति है, सौतेलपन नीति है, जिसके वजह से काम नहीं हो रहे हैं, कई रोड अधूरे पड़े हुये हैं । केन्द्रीय जो एजेंसी है, वह बैठा हुआ है, हम ने उन से कई बार आग्रह किया है, व्यक्तिगत पत्राचार भी किया है । लेकिन हमारे यहां भी कई सड़कों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है । हम फिर से आग्रह करेंगे कि उन्हें फिर से जल्द-से-जल्द बनाने का निर्देश देने की कृपा की जाय । महोदय, आज हम चाहते हैं कि बिहार और आगे बढ़े । हम अपने संसाधन से काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए । उसके लिये हम ने मुहिम छेड़ा, हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की अगुआई में हम दिल्ली तक गये और अंत में उन्हें बाध्य हो कर देना पडेगा, आज नहीं तो कल उन्हें झुकना पड़ेगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और हम और आगे बढ़ते रहेंगे । आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सेवा यात्रा कर रहे हैं । कोई विधायक, कोई नेता जिस गांव तक नहीं गया होगा, जिस गली में नहीं गया होगा, आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उस गली में जा रहे हैं, उस रोड में जा रहे हैं, उस टोले में जा रहे हैं, आज वे मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि मुख्य सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं । वहां की समस्या को देख रहे हैं । वहां की स्थिति को देख रहे हैं और उस के मुताबिक वहां की जो स्थिति है, वहां की जो चाहत हैं, उस के मुताबिक नीतियां बन रही है, सड़क बन रहे हैं, अन्य सुविधायें प्राप्त किये जा रहे हैं । पहले टेंडर में कई तरह की समस्यायें थी, आज टेंडर में परिवर्त्तन हो रहे हैं, आज ऑन लाईन टेंडर हो रहा है, आज २५लाख रूपये से ऊपर ई-टेंडरिंग की व्यवस्था है । सरल और पारदर्शी प्रक्रिया है और

....

सारा कार्यक्रम हमारे विभाग के जो प्रधान सचिव हैं और जितने भी अधिकारी हैं, उनके सहयोग से एक स्वच्छ माहौल बना है । आज किसी को कोई मनमानी करने का अधिकार नहीं है । कोई किसी पर जोर-जबर्दस्ती नहीं कर सकता है । बाहर के व्यक्ति भी यहां आ कर काम कर रहे हैं । दूसरे राज्य के व्यक्ति भी आ कर काम कर रहे हैं, उत्तर के व्यक्ति दक्षिण में और दक्षिण के व्यक्ति पूरब में जा कर काम कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बिना भय के एक अच्छे माहौल में काम रहे रहे हैं और बढ़िया ढंग से काम हो रहा है और उस काम का अनुश्रवण करने के लिये पटना में बैठे-बैठे ऑन लाईन सुविधा भी है । योजनाओं का अनुश्रवण भी किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के हस्ताक्षर अब डिजिटल सिगनेचर हो गये हैं । इसलिए पहले हम देखते थे, गांवों में जाते थे तो जब जे०सी०बी० मशीन आता था तो बच्चे-बूढ़े देखने के लिये दौड़ते थे कि क्या हो रहा है, आज जे०सी०बी० मशीन का बिहारमें प्रयोग हो रहा है ।

क्रमशः

टर्न-24/सत्येन्द्र/12-3-12

श्री जितेन्द्र कुमार(क्रमशः): इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हर पल विकास की बात सोचते हैं,विकास के बारे में सोचते हैं, वो सोचते ही नहीं,खाका ही तैयार नहीं करते,शिलान्यास ही नहीं करते, उस कार्य को अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं,उस कार्य को धरती पर लाने का काम करते हैं, उस कार्य को सम्पादित करने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। आज बिहार एक अनुकरणीय राज्य बन गया हैं। आज बिहार एक मॉडल राज्य बन गया है और नेपाल के जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार विकास का रौल मॉडल बन गया है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। कोई देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो बिहार के बारे में कि बिहार विकास का रौल मॉडल बन गया है तो ये कम गौरव और सम्मान की बात नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कई तरह की कमियां थी उसमें भी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब संवेदकों को समय सीमा के बीच घेरा जा रहा है कि आप अपना काम समय सीमा के अन्दर करें ताकि विकास हो,अच्छा विकास हो ताकि कम समय में जो समय सीमा दिया गया है उस पर विकास हो, हम चाहते हैं, हम चाहेंगे अधिकारियों से इस पर उचित कार्रवाई की जाय,संवेदकों को निर्देश दिया जाय कि वो काम समय सीमा के अन्दर करें ताकि जो जनहित में वो जल्द से जल्द कार्य कर सके और यही हमारी मंशा भी है, यही हमारे मुख्यमंत्री जी की और यही हमारे मंत्री जी की सोच है, आज गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास चल रहा है, आज अंचल स्तर पर गुणात्मक नियंत्रण प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव है और वो जल्द ही प्रयोगशाला खोला जायेगा ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो, देखा जा रहा है विपक्ष के लोग बोल रहे थे, हम तत्पर है, हम लगे हुए हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, बढ़िया रोड बने,काफी दिनों तक चले, हमारी मंशा है बिहार की तरक्की के लिए हमारी मंशा है बिहार के विकास के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक अच्छे सड़क का निर्माण भी होगा और हो भी रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार जो पहले धरातल में था आज पराकाष्ठा पर है, इसमें दो मत नहीं है। मुझे गौरव होता है कि हम ऐसे सौभाग्शाली विधायक हैं, हम तमाम लोग ऐसे सौभाग्यशाली विधायक है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके रहनुमायी में काम करने का मौका मिला, हम सौभाग्यशाली हैं कि इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज ग्लोबल मिट हो रहे हैं, आज बिहार के बारे में टिप्पणियां बदली है। पहले बिहार के बारे में कहा जाता था कि बिहार हासिये पर है,बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। आज बिहार वही बिहार है जो संभावनाओं का प्रदेश हो सकता है, आज बिहार वही है जो तरक्की का प्रदेश हो गया है, आज वही बिहार है जो विकास

के बारे में सोचते हैं, उस मॉडल को दूसरे अपनाते हैं, उस चीज को आत्मसात करते हैं ये कम गौरव की बात नहीं है इसलिए यह सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है इसलिए आज कोई जातपात की राजनीति नहीं होती है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि बिकास और आज समाज का अंतिम व्यक्ति भी चाह रहा है विकास इसलिए विकास जो विकास है जो हमारी मंशा है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, यह हमारा संकल्प है और ये काम हो रहा है। आज बिहार के बारे में मानसिकता बदली है और आज बिहार अन्य राज्यों के लिए नहीं, पूरी दूनिया में एक मोनो राज्य के रूप में उभरा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 2015 तक बिहार एक मॉडल राज्य बन जायेगा और एक विकसित राज्य बन जायेगा और ये आधुनिक बिहार जो बन रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक श्रेय जाता है इसलिए हम अपने तरफ से, अपने विधान-सभा क्षेत्र की ओर से, अस्थामा विधान-सभा की ओर से हम अपने नेता के प्रति, अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ हम आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। जय बिहार।

मो0 जावेद: अध्यक्ष महोदय,बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ग्रामीण कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई शक नहीं है अध्यक्ष महोदय कि बिहार में पिछले कुछ सालों से काफी सड़कें बनी है, जब से भारत सरकार यू0पी0ए0 के नेतृत्व में बनी है वहां पर। माननीय मंत्री जी को कागज के जरिये मैं बतलाना चाहता हूँ कि 2006 से 2012 तक लगभग 25 हजार कि0मी0 सड़क बना है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अकेले लगभग 15 हजार कि0मी0 बना है तो यह साफ जाहिर होता है कि जो यू0पी0ए0 की सरकार है, इसमें कोई जैसा सरकार बार-बार कहती है कि वो कोई अहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हिस्सा है जो हमें मिलना चाहिए लेकिन जिस तरह से कागज में विवाद और सरकार कभी इंकार नहीं करती कि जो योगदान है यू0पी0ए0 सरकार का तो मेरे ख्याल से मुखिद भी बोला जाय तो उचित होगा, मैं रिक्येस्ट करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय,हमारे कुछ साथी अभी कुछ सदस्यों ने बतलाया कि ग्रामीण कार्य विभाग से हर दिन 31 कि0मी0 सड़क बन रही है बहुत अच्छी बात है लेकिन हम तबतक तरक्की नहीं करेंगे, जबतक हम लोग अपना तुलना पिछले 15 साल से जो बार-बार दोहराया जाता है उसको हम छोड़ दें, अगर हम नजरिया वहीं तक रखेंगे तो हम कभी हिन्दुस्तान के बाकी राज्यों की तरह तरक्की नहीं कर पायेंगे, हमारा जो सरकार के तरफ से कागज दी गयी है ऐक्जेक्ट फिगर नहीं है सर,हर लाख लोगों पे बिहार में 113,आई एम

नौट भेरी स्योर,लगभग 113 कि0मी0 हर लाख लोगों पे बिहार में सड़क है और जब वही आंकड़ा पूरे हिन्दुस्तान का देखेंगे सर,तो 350 कि0मी0 प्रति लाख,अगर 31 कि0मी0 को 365 दिनों में गुणा कर दिया जाय तो 10000 कि0मी0 बनता है साल में और 10000 का मतलब हर लाख आदमी पर एक कि0मी0 जुड़ता है तो अगर बाकी हिन्दुस्तान में सड़क बंद हो जाय और हमारा यही रफ्तार रहा तो हमें 250 साल लगेंगे अन्य राज्यों के बराबर आने में और तब भी हमलोग अपने सरकार को अगर इस तरह वाहवाही देते रहेंगे तो कबतक हम मुकाबला करेंगे बाकी हिन्दुस्तान का, मेरा सवाल है सरकार से इसलिए मैं कांग्रेस के विधायक के नाते जो (व्यवधान)सर,बोलने का मौका दिया जाय, अभी तक हमलोग सुन रहे थे और मौका मिला है तो सुनना नहीं चाहते हैं और सर बड़ी तारीफ करते हैं हमारे रूलिंग पार्टी के विधायकगण लेकिन आप उनके बातों को देखिये कोई कंभिक्शन नहीं है, चूंकि तारीफ ही करनी है तो तारीफ किये जा रहे हैं ,कोई भी कंभीक्शन के साथ नहीं बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे। हमारी पार्टी चाहती है कि बिहार तरक्की करे लेकिन मैं बार-बार कहना चाहता हूँ अगर हम अपना तुलना पिछले 15 सालों से न कर के बिहार से जो विकसित राज्य है उससे मुकावला नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय,(व्यवधान)अभी भी 2012-13 का जो लक्ष्य है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री): महोदय,वो सच बोल रहे हैं,जब आदमी मरने लगता है तो पूरे जन्म के पाप को बोलता है इसलिए मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं पैकेज के मामले में या विशेष राज्य के दर्जा में, अगर अन्य राज्यों की तुलना में जो इनलोगों ने किया है बिहार को छोड़ दिया है मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हमको ढ़ाई सौ साल लगेगा अन्य राज्यों के मुकाबले आने में तो ये अपना पाप पोल रहे हैं, चार आदमी आ गये है और मरने वाले हैं तो सच्ची बात बोल रहे हैं।

मो0 जावेद: बहुत सिनियर मोस्ट हैं सर,और उनके बात पे हमारा कुछ कहना उचित नहीं होगा इसलिए मैं अपनी बात बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो ये तीसरी बार जीतने का मौका मिला है, माननीय जितने भी उधर बैठे हैं ज्यादातर 4-5 बार से ज्यादा जीते हैं और उन्होंने देखा नक्शा कि दो आदमी कभी सरकार बनाती है, चार आदमी फिर से सरकार बनाती है और अगले साल फिर हमलोग उधर बैठेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जो 2012-13 का इनका जो इरादा है अपने हिसाब से भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रम सड़क योजना के तहत हमलोग 13500 कि0मी0 बनायेंगे और वहीं पे चीफ मिनिष्टर सड़क से हमलोग (क्रमशः)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, नौजवान हैं । काहे के लिए चार साल इंतजार कीजिएगा ! आ जाइये । आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है पूर्वी क्षेत्र से। आ जाइये । आमंत्रण है ।

डा0 मो0 जावेद: धन्यवाद देना चाहता हूं । सर समझ नहीं पाए मेरा जो कहना था । हमलोग बहुमत में वहीं जाएंगे सर । पौने चार साल की बात है । थैंक यू सर । तो मेरा कहना है सर कि जो भी तरक्की हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी हमलोग बहुत पीछे हैं और स्पेशल अटेंशन, सरकार जो हिन्दुस्तान की सरकार है, उसका मिलना चाहिए । लेकिन वहीं पर जो स्पेशल पैकेज की बात की जा रही है उसके कुछ नॉर्म्स हैं और उसके नॉर्म्स के तहत कुछ कठिनाइयां हो रही हैं । उसके बावजूद भी जितना सहयोग एन0डी0ए0के वक्त में हमलोगों को मिलता आया है उससे कई चीजों में हमलोग को सौ-सौ गुणा से ज्यादा सहयोग मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है और इतना टोका-टोकी में क्या बताएं, मेरा, मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार जो हमारी छोटी दो-चार..

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री: हमलोगों से समय काट कर दे दीजिए । और बोलें । अच्छा बोल रहे हैं । अच्छा बोल रहे हैं, और बोलने दीजिए ।

डा0 मो0 जावेद: चीफ मिनिस्टर जी का बहुत-बहुत आभारी हूं । लेकिन मैंने शॉर्ट में अपनी जितनी बातें रखीं, उस पर गौर करने की मैं रिक्वेस्ट करता हूं । इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार इरादा रखती है कि बिहार आगे बढ़े लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज भी हमलोग सबसे नीचे हैं । एक मैं वाक्या देना चाहता हूं सर । एक बच्चा हर साल आ कर देखता है कि मुझे 50नम्बर था, दूसरे साल 60हो गया, 70हो गया, 80हो गया, 90हो गया, लेकिन जब आखरी बार 10में से 9 आदमी को नौकरी मिली, उसको नौकरी नहीं मिली इस वजह से कि वह हमेशा लास्ट आता था । हमलोगो को वो देखना है । हमलोग को अगर आगे बढ़ना है सर तो हमलोग को बाकी राज्यों में जैसा हो रहा है वैसे हो रहा है । गुजरात को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, ना ही महाराष्ट्रा को मिला, ना ही हरियाणा को मिला । उन्होंने अपने बल-बूते पर, अपने बल-वूते नहीं, हमारे लोगों की ताकत पर उन्होंने अपनी इमारत खड़ा की है । इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं सर कि हमारे बिहार को इतना आप

मजबूत कर दें, आपके पास चार साल का वक्त है, इसका भरपूर फायदा उठाएं आप और इतना मजबूत कर दें कि हमारे बिहार के जो लोग बाहर हैं वह अंदर आ जाएं । आप देखिएगा सर, दो साल में हमलोग बाकी स्टेट का मुकाबला कर लेंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं । आइन्दा अगर फिर समय दिया जाएगा, उस हिसाब से मैं तैयारी करके आऊंगा । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

डा0 अच्युतानन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग के 20अरब, 95करोड़ 97लाख 21हजार रूपए की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता है और उसमें सड़क आधारभूत संरचना का प्रमुख घटक है महोदय। विकसित सड़क और औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के विपणन के लिए बिना सड़क से, विकसित सड़क की कल्पना से एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज में खड़ा नहीं कर सकते । बिहार का जो विकास 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में जो बिहार आत्म-विश्वास के साथ विकास के दौड़ में आगे बढ़ा है, 2005के पहले विकास अपराध का पर्यायवाची था । बिहार में कहावत था, यदि पश्चिम बंगाल से, झारखंड राज्य से, उत्तरप्रदेश से कोई चार पहिया गाड़ी से हम आते हैं और जब बिहार में घुसते हिचकोला लेने लगे, तो लगता है बिहार आ गया है । आज वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि बिहार के एक कोना से दूसरे कोना तक हम पांच-छ: घंटा में राजधानी की सड़कों पर चले आवें । आज बिहार आत्म-विश्वास के दौड़ से गुजर रहा है । आज जावेद जी बोल रहे थे, माननीय जयराम रमेश, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, माननीय पी0सी0 जोशी, जो केन्द्र सरकार के मंत्री हैं, माननीय प्रणव मुखर्जी साहब जो केन्द्र के मंत्री हैं उन्होंने बिहार में आ कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है ग्रामीण कार्य विभाग में, कृषि के क्षेत्र में जो बिहार आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसकी प्रशंसा दिल्ली में बैठे केन्द्र के मंत्री ने बिहार में आ कर कर दिया है । महोदय, आज बिहार सरकार को विरासत में मिली है जर्जर सड़क और ध्वस्त कानून-व्यवस्था, उसको बिहार सरकार के

माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने पूरे आत्म-विश्वास के साथ पटरी पर लाया है । बिहार के अन्य देशों से ग्लोबल मीट से लेकर अन्य जगहों पर अन्य राज्यों के लोगों ने भी बिहार की प्रशंसा की है जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिचायक है।

महोदय, 2005 के पहले बिहार राज्य में सड़क प्रति एक लाख की आबादी पर 90कि0मी0 घनत्व था जबकि संपूर्ण भारत का घनत्व एक लाख की आबादी पर 257कि0मी0 था । बिहार में 2005 के पहले 90कि0मी0 घनत्व था और पूरे देश के अंदर 257कि0मी0 घनत्व था महोदय । उसी प्रकार से, बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ, तो बिहार में जो खराब जर्जर कानून-व्यवस्था थी, सड़क की जर्जर स्थिति थी, उससे निजात दिलाने के लिए एक संकल्प के साथ माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री डा0 भीम सिंह जी के कुशल व्यूह रचना में भी बिहार विकास के दौर पर आगे बढ़ा है महोदय । महोदय, 2005-06 में राज्य के सड़कों के निर्माण के व्यय मद में 263.23करोड़ रूपए, 2006-07 के व्यय के मद में 1662.93 करोड़ रूपए, 2007-08 में 2225.76करोड़ रूपए तथा 2008-09 में 2489.15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था महोदय । इसी राशि के व्यय में 2005-06 में जहां 415.48कि0मी0 सड़कें बनीं, वहीं पर 2006-07में 984.7कि0मी0, 2007-08 में 1913कि0मी0 तथा 2008-09 में 2417.14 कि0मी0 सड़कों का निर्माण किया गया है महोदय । महोदय, सरकार के सकारात्मक प्रयास के फलस्वरूप 2010-11 में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई 90कि0मी0 से बढ़ा कर 126.13कि0मी0 हो गई है । प्रति सौ कि0मी0 सड़कों की लंबाई पर 51कि0मी0 से बढ़ा कर 111.17कि0मी0 हो गई है महोदय । महोदय, 2005-06 में जहां राज्य की सड़कों की लंबाई 81,680कि0मी0 थी, जो 2011 तक 1,13,000कि0मी0 सड़कों का निर्माण हुआ है जिससे राष्ट्रीय उच्च पथों को छोड़ कर, राष्ट्रीय उच्च पथ में महोदय, 17,055कि0मी0 है महोदय । राज्य के ग्रामीण पथों का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अपनी सरकार आपके द्वार, ग्रामीण अधिरचना, विकास कोष, नाबार्ड, सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के विविध योजनाओं के अधीन होता है । वर्ष 2006-07 में महोदय, अब आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं

टर्न-25/12.3.2012/बिपिन ....

कि वर्षों से जो हमारा बफर रोड है, सलहा जन्दाहा से लेकर महनार रोड रेलवे स्टेशन तक का रोड वर्षों से लंबित है और हमारा दोनों प्रखंड जन्दाहा और महनार को जोड़ने वाला रोड है और एक और निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी, हमारे यहां जो महनार-मोहद्दीनगर पथ है वहां हसनपुर गांव से चकई से होते हुए मजलीसपुर होते हुए जो सड़क महनार में मिलती है वह सड़क तीन सालों से संवेदक के लापरवाही के कारण पड़ा हुआ है, कार्य नहीं हो रहा है । न संवेदक ब्लैक लिस्टेड हो रहा है और न कार्य प्रगति पर जा रहा है ... क्रमशः

डॉ० अच्युतानन्द : ...क्रमशः... उसी प्रकार से हवराहा से हसनपुर रोड है, इस प्रकार से जो हमारे गांव के कई-एक रोड हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस रोड पर ध्यान दिया जाय ।

अध्यक्ष : बैठिये । अब आप अपना स्थान ग्रहण करिये ।

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जाने, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किये जाने, युवा श्रम शक्ति तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था किये जाने, प्रवासी बिहारी श्रमिकों को प्रतिकूल समय में सहायता एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने, श्रमिकों के कल्याणार्थ स्वास्थ्य बीमा के लाभ दिये जाने, आदि से संबंधित रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के हित में अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना भी लागू की गई है । महोदय, इस योजना के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं, बाहर काम करते समय अगर दुर्घटना में उनकी मौत होती है तो सरकार उनके परिजनों को एक लाख रूपया अनुदान देती है । अपंगता की स्थिति में उनको ७५ हजार और आंशिक अपंगता की स्थिति में ३७.५ हजार रूपये अनुदान के रूप में राज्य सरकार देती है और देश में ऐसे बहुत कम राज्य हैं जो इन योजनाओं को लागू किये हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, गौरतलब है कि बिहार राज्य में कृषि क्षेत्र के बाद निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है । इनके हितों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार ने बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया है । बोर्ड द्वारा निर्माण मजदूरों के लिये कई कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, यथा- पेंशन, मातृत्व लाभ, विकलांगता पेंशन, मृत्यु हित लाभ, दाह-संस्कार सहायता, विवाह सहायता, परिवार पेंशन, स्वास्थ्य सहायता के लाभ, ऐसे कर्मकार कल्याण बोर्ड के जो हमारे मजदूर मेम्बर बन जाते हैं, उनको यह सुविधा देने का प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, निर्माण मजदूर जो कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकृत हैं, वे इन योजनाओं का लाभ लगातार ले रहे हैं । वर्ष २०११ में राज्य सरकार ने इस दिशा को और व्यापक करते हुये ऐसे मजदूरों के लिये भवन निर्माण, साइकिल एवं औजार क्रय हेतु एक विशेष अनुदान योजना चलायी है और जिसके माध्यम से १५ हजार रू० उन मजदूरों और कामगारों को हम देने का काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भवन सनिर्माण कर्मकार योजनान्तर्गत अबतक ९७२३ लाभान्वितों के बीच में १४,५८,४५,००० रू० की राशि वितरित की जा चुकी है और इसका लाभ मजदूर और निर्माण कार्य में लगे वे कामगार ले चुके हैं । इस योजना को निर्माण श्रमिकों के हित में व्यापक आधार प्रदान करने तथा बेहतर आयाम देने की दिशा में सरकार और विभाग लगातार प्रयासरत है । अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अन्तर्गत गरीबी-रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में ३० हजार रूपये तक

का मुफ्त ईलाज किये जाने की व्यवस्था है । इस योजनान्तर्गत अभी तक कुल ५६८ निजी क्षेत्र में एवं १० जन क्षेत्र के अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके माध्यम से अभी तक अध्यक्ष महोदय, ३,५४,६५४ लाभुकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जा चुका है, जिसके ऊपर २,७२,१८,८७,०१७ रू० राज्य सरकार उन मजदूरों के ऊपर और उन मजदूरों के स्वास्थ्य सुविधा के लिये खर्च कर चुकी है । महोदय, भू-मंडलीकरण के इस युग में देश और राज्यों में भी दूरी काफी सिमटती जा रही है और इसका परिणाम यह हुआ है कि रोजगार की तलाश आसान हो गये हैं किन्तु तकनीक के निरन्तर उन्नयन होते रहने से रोजगार के क्षेत्र अग्रतम तकनीक आधारित भी होते चले गये हैं । जाहिर है कि इस परिस्थिति का सामना करने के लिये राज्य के हर प्रक्षेत्र के गतिविधि में नियोजित होने वाले श्रम-शक्ति की दक्षता एवं कौशल को उन्नयन एवं बेहतर किये जाने, इस उद्देश्य से सरकार ने, इस विभाग ने राज्य के सभी ३८ जिलों को कम से कम एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आच्छादित कर दिया है । हर प्रमंडलीय मुख्यालय में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है और लगभग ४०० से ज्यादा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की भी प्रतिस्वीकृति दी जा चुकी है । जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत १०५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा १८१० कौशल विकास केन्द्र हेतु राज्य से निःशुल्क भूमि की अपेक्षा केन्द्र सरकार ने की थी । अध्यक्ष महोदय, हमने २०१० में ही भारत सरकार को २०५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं २२४५ कौशल विकास केन्द्र हेतु जमीन चिन्हित करके हमने सूची भेज दी है लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी तक भारत सरकार ने उसपर अग्रतर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया है । अध्यक्ष महोदय, बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र के कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०११-१२ में असंगठित कार्यक्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह नई योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है और इस योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में हम एक लाख रूपया, उनके अपंगता की स्थिति में हम ७५ हजार रूपया, आंशिक अपंगता की स्थिति में ३७.५ हजार रू० हम देने का काम करेंगे और यह एक काफी महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना खास करके असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों के लिये है । अध्यक्ष महोदय, दुर्घटना की स्थिति में घायल होने के फलस्वरूप अस्पताल में कम से कम पांच दिन तक भर्त्ती होने पर ५ हजार रू० ऐसे मजूदरों, कामगारों और शिल्पकारों को देने के लिये यह सरकार और यह विभाग प्रतिबद्ध है । अध्यक्ष महोदय, इस योजना के लिये भारत सरकार से भी भारतीय श्रम सम्मेलन में भाग लेते हुये हमने यह मांग किया था कि यह राज्य देश में प्रथम राज्य है जिसने इस योजना को लागू किया है । भारत सरकार भी इसके लिये सहयोग करे लेकिन अभी तक कोई स्वीकारात्मक और कोई सकारात्मक ऐसा पहल भारत सरकार से नहीं हुआ है । अगर भारत सरकार इसके लिये सहयोग करे तो हम इस योजना को मजबूती से कामगारों के लिये, शिल्पकारों के लिये और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिये लागू कर सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने श्रम विभाग के कुछ बातों को रखने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

सरकार का उत्तर

डॉ० भीम सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण पथों और पुलों का निर्माण करते हैं और इन्हीं ग्रामीण पथों और पुलों के निर्माण के सन्दर्भ में आज हमने सदन के समक्ष अनुदान मांग रखी और उसी अनुदान मांग के सन्दर्भ में आज यह सदन विमर्श कर रहा है, वाद-विवाद कर रहा है । इस वाद-विवाद के क्रम में जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, सुझाव दिया, शिकायत किया, हम सभी को शिरोधार्य करते हैं और वचन देते हैं कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हम उन सबका अनुपालन करेंगे और आपके सुझावों को लेकर ग्रामीण पथों और पुलों के निर्माण में हम आगे बढ़ेंगे ।

महोदय, सड़क और पुलों की महत्ता क्या है, आखिर सड़क और पुल हम क्यों बनाते हैं, सड़क और पुल मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक है । सड़कें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान बनाती हैं, सड़क और पुल दूरियाँ कम करती हैं और यातायात को सुगम बनाते हैं, विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी यह आवश्यक है कि कृषि, व्यवसाय और औद्योगिक विकास में भी ये सहायक हैं, सस्ती एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधा भी ये सड़कें और पुल मुहैया कराते हैं । रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज के लिये भी ये फीडर-लाईन का कार्य करते हैं, सभ्यता और सांस्कृतिक विकास के लिये भी यह सड़कें आवश्यक हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा को सुगम और राष्ट्रीय एकता-अखंडता को भी ये सड़कें सुनिश्चित करती हैं और ग्रामीण पथों का तो और भी महत्व है ।

...क्रमशः...